नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 049
दि. 21.11.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

ट्रंप ने खड़ा किया वैश्विक संकट, मोदी का कूटनीतिक सफर बना निर्णायक—जोहानिसबर्ग में नई विश्व व्यवस्था की आहट

(जीएनएस)। जोहानिसबर्ग इस समय केवल एक शहर नहीं, बल्कि बदलती विश्व राजनीति का विशाल कैनवास बन गया है। पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप पर जी–20 का आयोजन हो रहा है और उसके साथ ही कई ऐसी घटनाएँ घट रही हैं, जो आने वाले वर्षों में विश्व व्यवस्था की दिशा तय करने वाली हैं। दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे पर टिक गई हैं, लेकिन उससे भी अधिक तूल उस निर्णय को मिल रहा है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका पर आरोप लगाते हुए जी–20 समिट का खुला बहिष्कार कर दिया है। यह परिस्थिति केवल एक अनुपस्थिति नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका इस समूह का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जी–20 का भविष्य ही एक कूटनीतिक प्रश्न बन गया है—और उस प्रश्न का केंद्र भारत है।

2023 में भारत द्वारा दी गई जी–20 की थीम “एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य” ने दुनिया में एक नई संवेदनशीलता जगाई थी। भारत ने अपनी सभा को सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि भावनात्मक नैतिकता का मंच बनाया था। अब जब अमेरिका खुद सम्मेलन से दूर हो गया है, तब यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका अध्यक्षीय ‘बैटन’ किसे सौंपेगा? परंपरा कहती है कि यह बैटन अगले मेजबान देश—अमेरिका—को जाना चाहिए, लेकिन जब वह देश स्वयं शामिल ही नहीं है, तब दक्षिण अफ्रीका के सामने एक अभूतपूर्व दुविधा खड़ी हो गई है। यह दुनिया में पहली बार है जब जी–20 का औपचारिक हस्तांतरण ही अनिश्चितता का शिकार है। इस अनिश्चितता में ही भारत के लिए अवसर छिपा हुआ है—और कूटनीति का यही खेल उसे वैश्विक नेतृत्व के केंद्र में ला खड़ा करता है।

दक्षिण अफ्रीका पर इस समय भारी दबाव है। ट्रंप ने न केवल सम्मेलन को छोड़ा बल्कि ऐसे

संकेत भी दिए कि अमेरिका अन्य देशों से भी घोषणापत्र पर हस्ताक्षर न करने का आग्रह कर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो जी–20 की सामूहिकता की भावना को गहरा धक्का लगेगा और अगले वर्ष जब अमेरिका स्वयं इसकी अध्यक्षता संभालेगा, तब उसके पास उस भूमिका का नैतिक आधार कमजोर पड़ जाएगा। इन बदलते समीकरणों के बीच भारत एकमात्र ऐसी शक्ति के रूप में उभर रहा है जिसकी आवाज़ विश्व मंच पर स्वीकार्य भी है और प्रभावशाली भी। भारतीय विदेश मंत्रालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के तीनों प्रमुख सत्रों को संबोधित करेंगे, जिनमें समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह वही विषय हैं जिन्हें भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान वैश्विक प्राथमिकता सूची में शामिल करवाया था। भारत ने ही जी–20 में डिसास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की नींव रखी थी और अब दक्षिण अफ्रीका उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। यह केवल एक पहल का विस्तार नहीं, बल्कि भारत की दूरदर्शिता की अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी है। जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ के लगातार चार उभरते देशों—इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका—की अध्यक्षताओं की श्रृंखला का अंतिम अध्याय है। इन चारों देशों ने दुनिया को यह संदेश दिया कि जी–20 अब केवल विकसित राष्ट्रों की आर्थिक मंडली नहीं रहा; यह अब उन आवाज़ों का मंच बन चुका है जिन्हें दशकों तक वैश्विक निर्णयों में दरकिनार किया जाता रहा था। ऋण संकट, ऊर्जा संक्रमण, खाद्य असुरक्षा और जलवायु न्याय अब केवल विषय नहीं, बल्कि वैश्विक चेतना का हिस्सा बन गए हैं। इस परिवर्तन में भारत ने नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई है—न केवल अपनी पहल से, बल्कि अपनी व्यवहारिक और संतुलित कूटनीति से भी।

जब इलाज खुद बन गया खतरा: प्रयोगशालाओं में 211 दवाएं गुणवत्ता में फेल, लोगों की सेहत पर बड़ा सवाल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में दवाओं की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल एक बार फिर तेज़ हो गए हैं। अक्टूबर महीने की जिस रिपोर्ट का इंतजार स्वास्थ्य विभाग कर रहा था, उसने चिंताओं को और गहरा कर दिया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा जारी ड्रग अलर्ट में यह खुलासा हुआ है कि बाजार में उपलब्ध दवाओं के 211 नमूने गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतर सके। इसमें 63 नमूने केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं में जांच के दौरान फेल पाए गए, जबकि अलग-अलग राज्यों की प्रयोगशालाओं में 148 नमूने निकृष्ट गुणवत्ता यानी NSQ श्रेणी में पाए गए। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब देश दवाओं के निर्यात और घरेलू खपत दोनों के मामले में लगातार वृद्धि कर रहा है, और लोगों में भरोसा बनाए रखना सरकार और स्वास्थ्य प्रणाली की पहली जिम्मेदारी है।

जांच रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने बाजार से दवाओं के नमूने उठाकर उनकी बैच-वाइज टेस्टिंग की जाती है। कोई भी दवा केवल तभी निकृष्ट घोषित होती है जब वह अपने रासायनिक संघटन, शक्ति, शुद्धता, स्थिरता या निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरती। विशेषज्ञों के अनुसार यह जांच बेहद सूक्ष्म प्रक्रिया होती है और एक ही बैच का फेल होना पूरी कंपनी की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं करता। हालांकि यह भी सच है कि लगातार सामने आते NSQ नमूने इस बात का संकेत हैं कि उत्पादन स्तर पर सावधानी और निगरानी को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

अक्टूबर की रिपोर्ट में एक और चिंता बढ़ाने वाला मामला सामने आया है। बिहार और दिल्ली से कुल पांच नमूने ऐसे मिले हैं जिन्हें फर्जी यानी स्प्यूरियस श्रेणी में रखा गया है। फर्जी दवा वह होती है जिसके पैकेट, लेबल या ब्रांड नाम पर गलत कंपनी का नाम छापा जाता है, जबकि असल में वह किसी अनधिकृत या छिपे हुए निर्माता द्वारा तैयार की जाती है। ऐसी दवाएं न केवल इलाज को बेअसर बनाती हैं बल्कि गंभीर दुष्प्रभाव या जानलेवा खतरा भी पैदा कर सकती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि फर्जी दवाएं किसी भी देश की पब्लिक हेल्थ चेन के लिए सबसे बड़ा खतरा होती हैं, क्योंकि वे न सिर्फ इलाज को धोखा देती हैं बल्कि बीमारी की जड़ को अनियंत्रित कर देती हैं।

फिलहाल केंद्र और राज्यों के औषधि नियामक इन दवाओं को बाजार से हटाने की प्रक्रिया तेज़ी से चला रहे हैं। रिपोर्ट जारी होते ही संबंधित कंपनियों के पास नोटिस भेजे गए हैं और उन दवाओं के बैच को तुरंत वापस बुलाने के आदेश दिए गए हैं। कई मामलों में स्टॉकिस्टों और वितरकों को भी जानकारी भेजी जा चुकी है कि वे उन दवाओं की बिक्री तुरंत रोक दें। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया भारतीय औषधि बाजार में गुणवत्ता को बनाए रखने का एक निरंतर हिस्सा है, जिसका उद्देश्य केवल एक ही है—मरीजों को सुरक्षित, प्रभावी और भरोसेमंद दवाएं उपलब्ध कराना।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में टेस्टिंग नेटवर्क को काफी मजबूत किया गया है। सैंपलिंग बढ़ाई गई है और प्रयोगशालाओं की क्षमता को भी विस्तार दिया गया है। उनका कहना है कि दवाओं की निगरानी जितनी व्यापक होगी, उतनी ही तेजी से खराब दवाओं की पहचान संभव होगी। मंत्रालय का यह भी दावा है कि नियमित ड्रग अलर्ट जारी करना पारदर्शिता का हिस्सा है, ताकि आम लोगों और डॉक्टरों तक सही जानकारी पहुंच सके और वे सावधानी बरत सकें। इन सबके बीच आम लोगों को एक ही सलाह दी जा रही है कि दवाएं केवल मान्यता प्राप्त मेडिकल स्टोर से ही खरीदें, बिल जरूर लें और डॉक्टर की सलाह के बिना दवा का सेवन न करें। क्योंकि जब इलाज देने वाली गोलियां ही अपनी पहचान खोने लगें, तो सतर्क रहना ही सबसे पहली सुरक्षा बन जाता है।

2030 से पहले गरीबी में बड़ी गिरावट की कगार पर भारत, पर आधे बच्चों तक अभी भी ज़रूरी सेवाएं नहीं: यूनिसेफ रिपोर्ट

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति के बीच यूनिसेफ ने गुरुवार को जारी अपनी ताज़ा रिपोर्ट में भारत को एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में पेश किया है। ‘द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2025: एंडिंग चाइल्ड पॉवर्टी—आवर शेयर्ड इम्पेरेटिव’ रिपोर्ट के मुताबिक, भारत 2030 की तय समयसीमा से पहले बहुआयामी गरीबी को आधा करने के अपने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के बेहद करीब पहुंच चुका है। यह उपलब्धि देश में पिछले एक दशक में हुए आर्थिक सुधारों, कल्याणकारी योजनाओं, डिजिटल ढांचे के विस्तार और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की वजह से संभव हो पाई है। यूनिसेफ ने इसे एक तेज़ गति से बदलते भारत का संकेत बताया है, जो गरीबी उन्मूलन की दिशा में दुनिया के लिए प्रेरक कहानी बन सकता है।

हालांकि तस्वीर का दूसरा पक्ष चिंताजनक है। रिपोर्ट बताती है कि आज भी देश के 20.6 करोड़ बच्चे—जो भारत की कुल बाल आबादी का लगभग आधा हिस्सा है—शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ पानी, स्वच्छता और आवास जैसी छह अनिवार्य सेवाओं में से कम से कम एक तक पहुंच से वंचित हैं। ये वे बच्चे हैं जिनके सामने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बुनियादी चुनौतियाँ खड़ी हैं। झुग्गी बस्तियों से लेकर दूरदराज़ के ग्रामीण इलाकों तक, लाखों बच्चे ऐसी स्थितियों में पल रहे हैं जहाँ एक साधारण बीमारी भी परिवार को कर्ज़ में धकेल सकती है, और स्वच्छ पेयजल की कमी से उनके भविष्य का निर्माण शुरू होने से पहले ही कमजोर हो जाता है।

यूनिसेफ की रिपोर्ट इस बात पर भी रोशनी डालती है कि इन 20.6 करोड़ बच्चों में से केवल एक-तिहाई से भी कम यानी लगभग 6.2 करोड़ बच्चे दो या उससे अधिक आवश्यक सेवाओं से वंचित हैं। इसका मतलब यह है कि करोड़ों बच्चे बहुआयामी अभाव का सामना कर रहे हैं। शिक्षा न मिलने की वजह से सीखने की क्षमता सीमित हो जाती है, पोषण की कमी शारीरिक विकास को रोक देती है और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी उनके जीवन को लगातार जोखिम में रखती है। कई क्षेत्रों में बच्चे गंदे पानी, अस्वच्छ शौचालय या आवास के अभाव में बड़े होते हैं, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है और गरीबी से बाहर निकलना और कठिन हो जाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों—जैसे राष्ट्रीय पोषण मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, ग्रामीण आवास योजनाओं, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम और शिक्षा के सार्वभौमिकरण—की दिशा में बड़ी प्रगति की है। इन पहलों के प्रभाव से देश ने गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की है। लेकिन अभी भी बड़ी चुनौती उन समुदायों तक पहुंचना है जो भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से मुख्यधारा की सेवाओं से दूर रह गए हैं।

यूनिसेफ ने स्पष्ट किया है कि भारत के पास अवसरों की एक बेहद अहम खिड़की है, जहाँ नीतिगत हस्तक्षेपों को तेज़ करके और ज़मीनी स्तर की सेवाओं को अधिक समेकित करके लाखों बच्चों को बहुआयामी अभाव से बाहर निकाला जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में निवेश का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा, तो देश न केवल 2030 का लक्ष्य हासिल करेगा बल्कि बच्चों की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत सामाजिक आधार भी तैयार करेगा।

रिपोर्ट यह संकेत भी देती है कि भारत की प्रगति वैश्विक लड़ाई में निर्णायक साबित होगी, क्योंकि दुनिया में हर तीसरा गरीब बच्चा दक्षिण एशिया में है, और उनमें सबसे अधिक संख्या भारत की ही है। यदि भारत तेजी से गरीबी घटाता है, तो वैश्विक तस्वीर भी तेजी से बदल सकती है। इसलिए यह उपलब्धि केवल देश की सफलता नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी उम्मीद की किरण है। यूनिसेफ ने सरकार, समुदायों और निजी क्षेत्र से इस दिशा में मिलकर और अधिक ठोस प्रयास तेज़ करने की अपील की है, क्योंकि करोड़ों बच्चों की किस्मत बदलना केवल आर्थिक विकास का सवाल नहीं, बल्कि एक साझा मानवीय दायित्व है।

सियासत में हलचल, वाड्रा पर शिकंजा कसता गया: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दायर की चार्जशीट

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्र की जांच एजेंसियों और राजनीतिक हलकों में एक बार फिर खलबली मच गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने लंदन में रह रहे भगोड़े डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सेकेंड सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दायर यह चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रस्तुत की गई है, जहां इस पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को तय की गई है। चार्जशीट दाखिल होने की खबर सामने आते ही दिल्ली से लेकर लंदन तक इस केस की चर्चा तेज़ हो गई है, क्योंकि यह मामला लंबे समय से राजनीतिक बहस और आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र रहा है।

अधिकारियों के मुताबिक इस साल जुलाई में रॉबर्ट वाड्रा का बयान पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया था, जिसके बाद जांच के कई अहम पहलुओं पर एजेंसी ने दस्तावेज़ और लेन-देन से जुड़ी जानकारियों को खंगाला। अब ईडी ने दायर किए गए इस सप्लीमेंट्री दस्तावेज़ में वाड्रा को मामले का नौवां आरोपी बताया है। हालांकि अभी अदालत ने चार्जशीट पर औपचारिक संज्ञान नहीं लिया है। कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी कि वाड्रा को अदालत में पेश होना होगा या एजेंसी की ओर से और मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। चार्जशीट में जिन लेन-देन और कथित संपत्तियों का उल्लेख बताया जा रहा है, वे पहले से ही जांच के दायरे में थीं, लेकिन नए साक्ष्य और डिजिटल रिकॉर्ड मिलने के बाद ईडी ने इस मामले को एक और स्तर पर आगे बढ़ाया है। संजय भंडारी के खिलाफ पहले से ही कई देशों में जांच चल रही है और माना जाता है कि उसने रक्षा सौदों से जुड़े अनियमित तरीकों से बड़ी रकम विदेश भेजी। इन्हीं लेन-देन में वाड्रा की भूमिका की जांच एजेंसी लंबे समय से परख रही थी। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि भंडारी द्वारा खरीदी गई लंदन की संपत्तियों और उससे जुड़े भुगतान की परतें खोलते-खोलते एजेंसी कथित तौर पर वाड्रा की वित्तीय कड़ियों तक पहुंची। हालांकि वाड्रा इन आरोपों को लगातार खारिज करते रहे हैं और इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते रहे हैं। कांग्रेस भी बार-बार कह चुकी है कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस मामले ने एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ा दिया है, क्योंकि चार्जशीट दाखिल होना महज़ तकनीकी प्रक्रिया नहीं माना जाता, बल्कि यह जांच के अंतिम चरण के करीब पहुंचने का संकेत भी होता है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अभी अदालत द्वारा संज्ञान लेने के बाद ही यह साफ होगा कि जांच वाकई किस दिशा में आगे बढ़ेगी और क्या वाड्रा को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा। उधर राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली तारीख से पहले ईडी कुछ और दस्तावेज़ दाखिल कर सकती है या अदालत से कुछ और अनुमति मांग सकती है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि चुनावी मौसम नजदीक आते ही इस केस का प्रभाव और राजनीतिक बयानबाज़ी बढ़ सकती है। सत्ता पक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का उदाहरण बताएगा, वहीं विपक्ष इसे डराने और बदनाम करने की रणनीति करार देगा।

पाक सीमा के पास खेत में उतरा भारतीय UAV, इंजन की तकनीकी खामी से जमीं पर लानी पड़ी मशीन; वायुसेना ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षित किया एयरक्राफ्ट

(जीएनएस)। जोधपुर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित जैसलमेर जिले में गुरुवार को एक अप्रत्याशित घटना के दौरान भारतीय वायुसेना का रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (आरपीए) तकनीकी खामी आने के बाद एक खेत में उतर गया। यह घटना उस समय हुई जब आरपीए अपनी निर्धारित प्रशिक्षण उड़ान पर था और अचानक इंजन से संबंधित समस्या उत्पन्न हो गई। वायुसेना की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, पायलटों ने तत्काल नियंत्रण करते हुए इस एयरक्राफ्ट को एक सुरक्षित, खाली और समतल क्षेत्र की तलाश में नीचे लाने का निर्णय लिया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि या बड़े नुकसान की आशंका टल गई।

घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने इसे देखा और दोपहर करीब दो बजे इसकी सूचना पुलिस को दी। खेत में मौजूद किसानों ने बताया कि ड्रोन जैसी बड़ी मशीन को नीचे आते देख उन्हें पहले तो लगा कि कोई दुर्घटना हुई है, लेकिन पास पहुंचने पर पता चला कि यह वायुसेना का सर्विलांस ड्रोन है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने के बाद क्षेत्र को घेराबंदी कर लिया गया और वायुसेना तथा सेना के वरिष्ठ अधिकारी दल सहित मौके पर पहुंचे। एयरक्राफ्ट को सुरक्षित करने और उसकी तकनीकी जांच के लिए विशेष टीमों ने कार्य शुरू कर दिया।

स्थानीय निरीक्षण में यह सामने आया कि आरपीए जमीन को छूने के बाद कुछ दूरी तक घिसटता हुआ आगे बढ़ा, जिससे इसके आगे के हिस्से को नुकसान पहुंचा है। हालांकि पंख, सेंसर और पिछला ढांचा सुरक्षित मिला, जो दर्शाता है कि वायुसेना की टीम ने संकट के समय जिस सतर्कता और तकनीकी दक्षता के साथ सुरक्षित लैंडिंग करवाई, उसने एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। वायुसेना ने कहा है कि इस अभियान में उनके ऑपरेटरों ने आपात परिस्थितियों का उत्कृष्ट प्रबंधन किया और जिस स्थान पर एयरक्राफ्ट उतारा गया, वह जनविहीन था, जिससे किसी भी नागरिक को खतरा नहीं हुआ।

यह आरपीए भारतीय वायुसेना द्वारा सीमा क्षेत्रों में निगरानी, टोही मिशन और तकनीकी सर्विलांस जैसे उद्देश्यों के लिए नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। पड़ोसी देश की संवेदनशील सीमा से इसकी निकटता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और कुछ समय के लिए आसपास के इलाकों की भी जांच की गई। अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक जांच में यह मामला पूरी तरह तकनीकी खामी का लग रहा है और इसके पीछे किसी बाहरी हस्तक्षेप के संकेत नहीं मिले हैं। एयरक्राफ्ट को आगे की जांच और मरम्मत के लिए वायुसेना के तकनीकी बेस में ले जाया जाएगा, जहां विशेषज्ञ इसकी इंजन प्रणाली और कंट्रोल यूनिट की विस्तृत जांच करेंगे।

इस तरह की घटनाएं सैन्य प्रशिक्षण में असामान्य नहीं मानी जातीं, क्योंकि हाई-टेक सिस्टम में समय-समय पर तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि वायुसेना अक्सर ऐसे उपकरणों को आबादी से दूर सुरक्षित क्षेत्रों में उड़ाती है ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में जोखिम को कम किया जा सके। गुरुवार की घटना में जिस तरह त्वरित प्रतिक्रिया और आपात प्रबंधन किया गया, उससे यह स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना की आपदा-सहनशीलता और त्वरित कार्रवाई क्षमता अत्यंत मजबूत है। मामले की तकनीकी जांच पूरी होने के बाद वायुसेना विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगी और आवश्यकता पड़ने पर सिस्टम में सुधार के कदम उठाए जाएंगे।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

विकास की रोशनी दूर करेगी हिंसा का अंधेरा

इसमें दो राय नहीं है कि शीर्ष माओवादी कमांडर हिडमा का मुठभेड़ में मारा जाना वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ देश की दशकों पुरानी लड़ाई में निर्णायक सफलताओं में से एक है। संगठन के शीर्ष नेतृत्व पर प्रहार से देश नक्सली हिंसा से मुक्ति की राह में कामयाबी की तरफ बढ़ा है। लगभग तीन दशकों तक हिडमा बस्तर में चौंकाने वाली रणनीतियों से बड़े हमलों को अंजाम देता रहा है। बताते हैं कि वह सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हुए सबसे घातक हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा हिडमा व उसकी पत्नी समेत छह नक्सलियों को मार गिराना केंद्र सरकार की उस रणनीति की सफलता को दर्शाता है, जिसमें 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया था। इसी साल मार्च में बीजापुर में जब 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था तब गृहमंत्री अमित शाह ने उनके फैसले का स्वागत करते हुए सभी का पुनर्वास करके, उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने की बात कही थी। निस्संदेह, हिडमा का सफाया नक्सलवादी संचालन ढांचे के खात्मे और भारत में उग्रवाद विरोधी तंत्र की एक महत्वपूर्ण जीत का संकेत है। गुरिल्ला आर्मी की बटालियन-1 के कमांडर के रूप में हिडमा का उदय- वंचित युवाओं की भर्ती करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और हथियार बनाने की उग्रवादी क्षमता का प्रतीक रहा है। उसकी गिनती सबसे खूंखार नक्सलवादी कमांडर के रूप में होती रही है। अब वर्ष 2010 का दंतेवाड़ा हमला हो या 2013 का झीरम घाटी हमला, पिछले बीस वर्षों में हुए लगभग सभी बड़े नक्सली हमलों के पीछे हिडमा की रणनीति बतायी जाती है। वहीं दूसरी ओर इन हमलों ने भारत की सुरक्षा रणनीति को नया रूप दिया। इससे पहले इसी साल मई में सुरक्षाबलों ने माओवादी संगठन के जनरल सक्रेटरी बसवराजू को भी मार गिराया था। वहीं इस साल विभिन्न मुठभेड़ों में तीन सौ से अधिक नक्सली मारे जाने से नक्सलवाद छोटे इलाके में सिमटा है।

निस्संदेह, सुरक्षा बलों की तत्परता और सुनियोजित अभियानों से नक्सलवाद कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन जरूरत उन परिस्थितियों को दूर करने की है, जिन्होंने नक्सलवाद को जन्म दिया। आवश्यकता उन मुद्दों के समाधान की है, जिसके चलते माओवाद को जड़ें जमाने का मौका मिला। बस्तर का अधिकांश क्षेत्र लगातार विकास की विसंगतियों, खनन से संसाधनों के मनमाने दोहन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण विस्थापन व जनजातीय समुदायों और राज्य के बीच विश्वास की कमी से जूझता रहा है। अभी भी आदिवासियों की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, गुणवत्तापूर्ण स्कूलों, भूमि अभिलेखों और कल्याणकारी योजनाओं तक पूरी तरह पहुंच नहीं बन पायी है। दूर-दराज के कई गांवों में ग्रामीणों को प्रशासन का अनुभव नागरिक संस्थानों के बजाय सुरक्षा बलों की मौजूदगी से ही होता है। दरअसल, विकास की नीतियों से जुड़े वायदों और हकीकत का अंतर ही आदिवासियों में असंतोष को बढ़ाता है। भले ही माओवाद का प्रभाव कम हो जाए। वास्तव में जब तक शासन जिम्मेदार, जवाबदेह और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील नहीं बन पाता, तब तक माओवादी संस्कृति के पनपने की आशंकाएं बनी रहेंगी। दरअसल,क्षेत्र में तंत्र की अनुपस्थिति ने ही चरमपंथियों को आदिवासियों के रक्षक के रूप में पेश करने का मौका दिया। निस्संदेह, सुरक्षा बलों ने माओवाद के खात्मे की दिशा में बड़ा काम कर दिया है, अब राज्यों के पास इस रणनीतिक जीत को स्थायी शांति में बदलने का अच्छा अवसर है। इसकी प्राप्ति के लिये यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि सड़कें, स्कूल, नागरिक अधिकार व आजीविका बस्तर के वनाच्छादित इलाकों तक पहुंचे। तभी देश नक्सली हिंसा के दंश से भविष्य में मुक्त रह पाएगा। अभी नक्सवादियों पर जो चौतरफा दबाव बना है और जिस तरह से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उसके निहितार्थों को स्थायी बनाने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में जारी सघन अभियान से बच निकलकर नक्सली देश के अन्य राज्यों में नये ठिकाने न तलाश लें। साथ ही समर्पण करने वाले नक्सलियों को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करने के संवेदनशील प्रयास भी बेहद जरूरी हैं।

मतदाता की जागरूकता से ही निरंकुशता पर अंकुश

> “यदि किसी नेता को यह भ्रम होने लगे कि वह सेवक नहीं, मालिक है तो यह एक तरह से जनतंत्र को नकारना ही होगा। ऐसा व्यक्ति बड़ी आसानी से निरंकुश हो सकता है, और यह स्थिति किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।

बिहार का चुनाव भी हो गया। परिणाम कुल मिलाकर अप्रत्याशित तो रहे पर इतने अप्रत्याशित नहीं कि उन पर हैरान ही हुआ जाये। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह के हालात बनते दिख रहे थे, उनमें कहीं न कहीं यह तो लगने लगा था कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को जीत मिल सकती है पर इतनी बड़ी जीत होगी, ऐसा नहीं लग रहा था। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि महागठबंधन की इतनी बुरी हार होगी, ऐसा भी नहीं लग रहा था। पर ऐसा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी जीत और राजद की ऐसी हार अप्रत्याशित तो थी, पर यह भी समझना ज़रूरी है कि यह स्थिति चिंताजनक भी है। सत्तारूढ़ पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं, देश में जनतंत्र के भविष्य के लिए यह स्थिति चिंताजनक है।

हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था में मजबूत सरकार का होना कतई चिंता की बात नहीं है, पर विपक्ष का इतना कमज़ोर हो जाना निश्चित रूप से चिंता की बात होनी चाहिए। यह पहली बार नहीं है कि किसी विधानसभा में, या फिर संसद में भी, असंतुलित परिणाम आये हैं–इतने असंतुलित परिणाम कहना चाहिए इसे! और यह 'इतने' शब्द यहां चिंता की बात को प्रकट करता है। ऐसी जीत जीतने वाले को अति विश्वास से भर देती है और यह अति विश्वास उसे, कुछ भी कर सकता हूं, का अहसास दिलाने वाला होता है। अच्छा और मज़बूत होने का अहसास ग़लत नहीं है, पर यह मज़बूती यदि घमंड में बदल जाती है तो इसे सही नहीं कहा जा सकता। सही नहीं होने का यह खतरा आज हमारे जनतंत्र पर मंडरा रहा है।

ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थितियां पहले कभी नहीं बनीं। राज्यों में भी ऐसा हो चुका है, और केंद्र में भी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब चुनाव हुए थे तो राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को लोकसभा में चार सौ

से अधिक सीटें मिली थीं। अति घमंड की स्थिति बन सकती थी। पर तब कांग्रेस को यह अहसास था कि उसे सहानुभूति की लहर का लाभ मिला है। पर अब बिहार में भाजपा की जीत के मामले में ऐसी बात नहीं है। उसके पक्ष में कोई 'सहानुभूति लहर' नहीं थी। भाजपा और 'जदयू' की जीत तथा कांग्रेस और राजद की हार के कारणों पर विचार होगा और भविष्य में भी होता रहेगा। पर इस बात पर विचार होना ज़रूरी है कि इस तरह के अप्रत्याशित परिणाम चिंता का कारण भी होने चाहिए। कोई जीत इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि जीतने वाला स्वयं को अपराजेय समझने लगे और कोई भी हार इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए कि हारने वाले को यह लगने लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। बहरहाल, बिहार के इन चुनाव- परिणामों पर दो दृष्टियों से विचार होना चाहिए–पहले तो इस दृष्टि से कि क्या जीतने वाला अपनी श्रेष्ठता के कारणों से ही जीता है और दूसरी यह कि हारने वाला कहां चूक गया। भाजपा की जीत पर उंगली उठाने वालों का मानना है कि चुनाव में ऊंच-नीच हुई है। यह सवाल चुनाव आयोग पर भी है। उस पर आरोप लग रहा है कि उसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों, से भाजपा की जीत में मदद की है। इस तरह के आरोप मतदान से पहले भी लगते रहे थे, अब भी लग रहे हैं। ऐसी ही किसी मदद से इनकार के अलावा और कोई ठोस प्रमाण चुनाव आयोग ने नहीं दिया। चुनाव आयोग से यह अपेक्षा और उम्मीद की जा रही है कि वह यह बतायेगा कि भाजपा की बिहार सरकार को एक करोड़ 10 लाख महिला मतदाताओं को चुनाव से ठीक पहले दस-दस हजार रुपये नकद सहायता देने से रोका क्यों नहीं गया? पहले भी सरकारें नकद रेवड़ियां बांटती रही हैं। महाराष्ट्र के पिछले चुनाव में भी 'लाड़ली बहिना' को नकद सहायता देने के आरोप लगे थे। तब आरोप यह भी था कि भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने तब हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव एक साथ नहीं कराये थे, जबकि पिछले 15 सालों से इन दोनों राज्यों में चुनाव साथ-साथ होते आये हैं। चुनाव आयोग पर आरोप लगा था कि महाराष्ट्र में चुनाव तीन-चार महीने टालकर उसने महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार को रेवड़ियां बांटने का पर्याप्त समय दिया था। आयोग ने इस आरोप का कोई विश्वसनीय उत्तर नहीं दिया था।

जहां तक बिहार में हारने वाले की चूक का सवाल है, इस बात के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं कि कांग्रेस और राजद दोनों ने वह ताकत नहीं लगायी जो जीतने के लिए ज़रूरी होती है। सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में दोनों ने एक तरह से अत्यधिक देरी की थी। नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत आरोप लगाने की नीति भी गलत सिद्ध हुई। उधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का चुनावों को हल्के में लेने का रवैया भी कुल मिलाकर आत्मघाती ही सिद्ध हुआ। महागठबंधन के साथी सहयोगियों को अपनी कमज़ोरी और गलतियों पर गंभीरता से विचार करना होगा। पर गंभीरता से विचार करने का एक मुद्दा और भी है, और उसका सीधा रिश्ता हमारे जनतंत्र के भविष्य से है। बिहार विधानसभा में 200 से अधिक सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगियों के जीतने का एक अर्थ सत्तारूढ़ पक्ष का ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर होना भी है। ऐसी जीत की उम्मीद तो भाजपा को भी नहीं थी। पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने भी मतगणना के पूर्व अधिकतम 160 सीटें जीतने की बात कही थी– अर्थात् उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अधिक सीटें मिल सकती हैं। कारण कुछ भी रहे हों, चुनाव परिणामों ने भाजपा को अति विश्वास की सीमा तक तो पहुंचा ही दिया है।

बात सिर्फ अति विश्वास तक ही सीमित नहीं है। ऐसी स्थिति के दो परिणाम हो सकते हैं– पहला तो यह कि ऐसी जीत वाले दल या नेता को यह लगने लगता है कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता और दूसरा यह कि ऐसी जीत वाले नेता को अपने भूतो न भविष्यति होने का भ्रम होने लगता है। जनतंत्र की दृष्टि से यह दोनों परिणाम खतरनाक हैं। जनतंत्र का मतलब किसी नेता या दल का नहीं, जनता का शासन होता है। ऐसे में यदि किसी नेता को यह लगने लगे कि वह सर्वशक्तिमान है, अजेय है, तो यह उस मतदाता का घोर अपमान है, जो अपना नेता चुनता है। यह व्यक्ति वस्तुतः नेता नहीं होता, मतदाता का प्रतिनिधि होता है, जनता की ओर से चुना गया जनतंत्र का सेवक, जो जनता के लिए काम करता है।

जनतंत्र को जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार कहा जाता है। यदि किसी नेता को यह भ्रम होने लगे कि वह सेवक नहीं, मालिक है तो यह एक तरह से जनतंत्र को नकारना ही होगा। ऐसा व्यक्ति बड़ी आसानी से निरंकुश हो सकता है, और यह स्थिति किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर जनता का अंकुश ज़रूरी है, और ऐसा व्यक्ति कभी भी अंकुश स्वीकार करना नहीं चाहेगा!

इसलिए जनतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी माना जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में एक बार संसद में विपक्ष बहुत कमज़ोर हो गया था। तब उन्होंने सदन में कांग्रेसी सदस्यों से कहा था कि वे सरकार के काम-काज पर निगाह रखें, ताकि सरकार या प्रधानमंत्री निरंकुश न हो जाये। यह निरंकुशता चुनावी तानाशाही तक ले जा सकती है। आज दुनिया के कई देशों में यह प्रवृत्ति पनप रही है। जनतांत्रिक मूल्यों-आदर्शों का तकाज़ा है कि इस प्रवृत्ति को रोका जाये। बिहार के चुनाव-परिणामों को इस दृष्टि से भी देखा जाना ज़रूरी है।

प्रेरणा

बलिदान की धूल में चमकता एक बालक और उसके संस्कारों की कहानी

सुबह की सुनहरी रोशनी धीरे-धीरे मैदानों पर उतर रही थी। स्कूल का पुराना-सा बस किसी थके हुए घोड़े की तरह गरजता हुआ सड़क पर आगे बढ़ रहा था। खिड़कियों से आती हवा बच्चों के बालों को उलझा रही थी, पर हाईस्कूल का वह छात्र एकदम शांत बैठा था। आज कक्षा का ऐतिहासिक भ्रमण था—वह स्थान जहाँ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत वीरों ने अपने प्राण देश को समर्पित कर दिए थे।

बस जैसे-जैसे उस स्थल के करीब आती गई, छात्र के भीतर का उत्साह किसी अदृश्य हाथ से पकड़ा गया हो—वह गंभीर होता गया। उसके मन में यह केवल पिकनिक नहीं था, यह कोई यज्ञस्थल था जहाँ शहीदों की अंतिम साँसें अब भी हवा में तैर रही होंगी।

बस रुकी। सभी बच्चे उतरे और सामने पत्थरों से बनी उस जगह को देखते हुए ऊपर चढ़ने लगे। वहाँ एक प्रतिमा खड़ी थी—एक वीर का चेहरा, दृढ़ नजरें, संघर्ष और त्याग से भरी आँखें। प्रतिमा के पास खड़े होकर छात्र को लगा कि उन आँखों में क्रांति की आग अब भी जीवित है—उस आग ने उस भूमि को पवित्र बना दिया था।

शिक्षक ने सबको पास बुलाया और वीरों की गाथाएँ सुनानी शुरू कीं—कैसे उन जवानों ने अत्याचारों को सहा, कैसे उन्होंने अपनों को छोड़कर मातृभूमि को गले लगाया, कैसे भारी जुल्मों के बीच भी वे डटे रहे, और कैसे उन्होंने हँसते हुए फाँसी का फंदा चूमा।

हर शब्द उस बालक के दिल पर दस्तक देता गया। उसके भीतर एक अजीब-सी कंपकंपी दौड़ गई। उसे लगा जैसे धरती अभी भी उन कदमों की थरथराहट को याद कर रही है, जिन वीरों ने इसी मिट्टी पर आखिरी

बार चलकर अपनी शहादत पूर्ण की थी।

कुछ देर बाद वह धीरे-धीरे सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया और पार्क की उस पतली पगडंडी के पास रखी सीमेंट की बेंच पर बैठ गया। उसने जूते पहने, पर उसके कदमों में संकोच था—जैसे वह किसी पवित्र स्थान के नियमों को अनजाने में तोड़ रहा हो। उसकी आँखें फिर से प्रतिमा पर टिक गईं। हवाओं में हल्की-सी आहट थी, मानो प्रतिमा उससे कह रही हो, "सम्मान, यही मेरी सबसे बड़ी माँग है।" अचानक उसकी नज़र उन आगंतुकों पर पड़ी—तीन-चार लोग बिना किसी चिंता के सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। उनमें से एक ने हैट पहन रखी थी और हाथ में कैमरा था। बाकी दो लोग सिगार पीते हुए बेपरवाही से हँसते-बोलते आगे बढ़ रहे थे। वे सीधे प्रतिमा के बिल्कुल पास जाकर खड़े हो गए—जूते पहने, धुआँ उड़ाते, जैसे यह स्थान बस एक पर्यटन स्थल हो।

यह दृश्य उस छात्र के भीतर गरजते तूफ़ान जैसा था। उसके संस्कारों में यह गहराई से बैठा था कि पवित्र भूमि पर जूते पहनकर जाना अपमान है। यह वह जगह थी जहाँ लोगों ने अपनी अंतिम साँसें देश के नाम की थीं—यह कोई सामान्य पत्थर नहीं था, बल्कि बलिदान की आग से तपकर जन्मी भूमि थी।

वह बेंच से उठ खड़ा हुआ। धीरे-धीरे उन लोगों के पास गया। आवाज़ में कसक थी, पर सम्मान और दृढ़ता भी थी। उसने निडर लेकिन विनम्र स्वर में कहा—

"आपको यहाँ नंगे पैर आना चाहिए था। यह स्थान बहुत पवित्र है। ऐसे स्थलों पर जूते-चप्पल उतार देना सम्मान होता है यह कोई साधारण प्रतिमा नहीं, बलिदान की प्रतीक है।"

उस समय वह सिर्फ एक किशोर था, पर उसके शब्दों में वह गहराई थी जो किसी तपे हुए मन में ही जन्म लेती है। वह लोगों को डाँट नहीं रहा था, बल्कि उन्हें वह भाव सिखा रहा था जिसे वह स्वयं जी रहा था।

शायद उन आगंतुकों को एक पल को ही सही, पर अपनी भूल का एहसास हुआ होगा। पर उससे भी बड़ी बात यह थी कि उस छात्र के भीतर मौजूद संवेदनशीलता आने वाले समय का परिचय दे रही थी। वह दुनिया को केवल आँखों से नहीं, आत्मा से देखता था। वर्ष बीतते गए। वह बालक बड़ा हुआ। उसके भीतर की वही संवेदना उसकी दृष्टि में उतरती गई—कहानियों में, फ्रेमों में, कैमरे की आँख में। उसकी कला सिर्फ दृश्य नहीं, भावना बन गई। उसका कैमरा केवल चित्र नहीं कैद करता था—वह मनुष्य की आत्मा को पकड़ लेता था।

और फिर एक दिन दुनिया ने उसी किशोर को पहचाना—सत्यजीत रे के रूप में।

वह फिल्मकार, जिसने भारतीय सिनेमा को मानवता की आँखों से देखने की शक्ति दी।

यह केवल एक घटना नहीं थी—यह उस प्रकाश का जन्म था जो संस्कारों से उपजता है।

संस्कार कोई नियम-पुस्तक नहीं—वे मनुष्य की आत्मा में जगा हुआ वह सम्मान हैं जो मौन रहते हुए भी जीवन को ऊँचा उठा देते हैं।

यही संस्कारों की असली ताकत है—वे मनुष्य को भीतर से इतना उज्ज्वल बना देते हैं कि उसकी मौजूदगी ही दुनिया में एक नई रोशनी लेकर आती है।

ट्रिब्यूनल सुधार और राष्ट्रपति संदर्भ संबंधी फैसले संवैधानिक मर्यादा और न्यायिक संयम की मिसाल

भारत की संवैधानिक संरचना में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन सदैव एक संवेदनशील विषय रहा है। दो दिनों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दो महत्वपूर्ण फैसलों ने इस संतुलन पर नई बहसों को जन्म दिया है। एक ओर न्यायालय ने न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रमुख प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराकर संसद और केंद्र सरकार को कठोर संदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत भेजे गए संदर्भ पर अपनी राय देते हुए न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल पर अदालत कोई बाध्यकारी समय-सीमा थोप सकती है। इन दोनों फैसलों को मिलाकर देखें तो न्यायालय ने एक ओर कार्यपालिका के हस्तक्षेप से न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा की है, जबकि दूसरी ओर अपने अधिकार-क्षेत्र की सीमाएँ भी रेखांकित की हैं। न्यायाधिकरण संबंधी फैसले की बात करें तो 19 नवंबर को दिए गए 137 पृष्ठों के निर्णय में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने साफ कहा है कि संसद पहले से रद्द किए गए प्रावधानों को मामूली बदलावों के साथ दोबारा पेश कर न्यायिक फैसलों को दरकिनार नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि सरकार बार-बार उन्हीं प्रावधानों को अध्यादेश और फिर कानून के रूप में लागू करती रही, जिन पर न्यायालय स्पष्ट रूप से ऐतराज जता चुका था। यह प्रवृत्ति विधायी अवहेलना (legislative overruling) के रूप में व्याख्यायित की गई— अर्थात, बिना वास्तविक सुधार किए केवल प्रतीकात्मक परिवर्तन कर न्यायालय की बात को निष्प्रभावी करने का प्रयास।

यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और संस्थागत मर्यादा को ठोस आधार देता है। न्यायाधिकरण सरकार के अंगों के विरुद्ध भी निर्णय लेते हैं; ऐसे में उनकी नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा-शर्तें यदि सरकार के नियंत्रण में हों, तो न्यायिक निष्पक्षता खतरे में पड़ सकती है। न्यायालय ने इस अधिनियम को शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) और न्यायिक स्वतंत्रता (Judicial Independence) के सिद्धांतों का उल्लंघन करार देते हुए रद्द कर दिया। यह स्पष्ट संकेत है कि संसद कानून तो बना सकती है, लेकिन न्यायपालिका की मूलभूत स्वतंत्रता को नियंत्रण में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

दूसरा महत्वपूर्ण फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए संवैधानिक संदर्भ पर आया। न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न था— क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति पर यह बाध्यता हो सकती है कि वे किसी बिल पर तय समय-सीमा में निर्णय दें? मुख्य न्यायाधीश गवई तथा न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी.एस. नरसिंह और ए.एस. चंदुरकर की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय राज्यपाल/राष्ट्रपति पर कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं थोप सकता। यह स्पष्ट है कि "Deemed Assent" अर्थात समय बीतने पर बिल को स्वतः मंजूर मान लेने की अवधारणा असंवैधानिक है, क्योंकि यह कार्यपालिका की भूमिका को न्यायपालिका द्वारा हड़पने जैसा होगा। हाँ, यदि लंबे समय तक अनिश्चित देरी हो, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हो, तो न्यायालय सीमित दायरे में यह निर्देश दे सकता है कि राज्यपाल अपनी जिम्मेदारी निभाएँ, लेकिन यह निर्देश विवेकाधिकार के उपयोग पर टिप्पणी नहीं करेगा।

इस फैसले से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली यह कि न्यायालय ने स्वयं पर अंकुश लगाते हुए साफ किया कि कार्यपालिका के संवैधानिक अधिकारों में दखल की सीमा तय है। दूसरी बात यह है कि राज्यपालों की ओर से बिलों को महीनों तक रोककर रखने की आलोचना को भी न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और समाधान के रूप में सीमित न्यायिक समीक्षा का दरवाज़ा खुला रखा है। यह संतुलन स्थापित करना आसान नहीं था। एक ओर राज्यों— विशेषकर तमिलनाडु, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने तर्क दिया कि राज्यपालों द्वारा बिलों को रोकना लोकतंत्र-विरोधी है। दूसरी ओर, केंद्र ने कहा कि अदालतें समय-सीमा तय करके कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकतीं। अंततः न्यायालय ने वही रास्ता चुना जो भारतीय संविधान की आत्मा के अनुरूप है यानि संविधान ने समय-सीमा नहीं तय की है, इसलिए अदालत भी इसे तय नहीं करेगी।

इन दोनों फैसलों में न्यायालय का स्वर पूरी तरह एक जैसा नहीं है। एक तरफ उसने संसद को तीखी चेतावनी दी, दूसरी तरफ उसने खुद अपनी सीमाओं को स्वीकार किया। यही दोहरी भूमिका भारतीय लोकतंत्र को संतुलित बनाती है। न्यायालय संदेश दे रहा है कि न्यायिक स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का आघात बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन संविधान में जो अधिकार अन्य अंगों को दिए गए हैं, उन पर न्यायपालिका कब्जा नहीं करेगी।

इन फैसलों की समय-सीमा भी रोचक है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। उनके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इन दोनों महत्वपूर्ण संवैधानिक फैसलों पर गवई और सूर्यकांत दोनों की निर्णायक भूमिका भविष्य की न्यायिक दिशा के संकेत देती है— विशेषकर केंद्र–राज्य संबंधों और न्यायिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में।

बहरहाल, संविधान ने भारत को एक संतुलित संरचना दी है— न्यायपालिका स्वतंत्र हो, कार्यपालिका जिम्मेदार हो और विधायिका जनता के प्रति उत्तरदायी हो। इन दोनों फैसलों ने इस संतुलन को और भी स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। जहाँ न्यायालय ने संसद को बताया कि वह न्यायिक आदेशों को दरकिनार नहीं कर सकती, वहीं राज्यपालों और राष्ट्रपति की संवैधानिक गरिमा को भी मान्यता दी, यह कहते हुए कि समय-सीमा थोपना न्यायपालिका के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है। इन फैसलों के साथ भारत का लोकतंत्र एक बार फिर यह साबित करता है कि संस्थाएँ तभी मजबूत होती हैं जब वे एक-दूसरे की सीमाओं और स्वतंत्रता का सम्मान करें।

अभियान

नारद के अहंकार का उदय, भगवानों की चेतावनी और एक दिव्य लीला का

कैलाश पर्वत की नीरव श्वेत शांति के बीच उस दिन कुछ ऐसा घटा था, जो देवताओं की दृष्टि में सामान्य नहीं था। नारद मुनि जैसे तपोनिष्ठ, ब्रह्मचर्यव्रती, और सतत हरिनाम-जप में रमे रहने वाले देवर्षि के हृदय में एक सूक्ष्म but भयंकर परिवर्तन पनप चुका था। उनकी आँखों में तेज तो वैसा ही था, पर भीतर कहीं अहंकार का धुआँ उठने लगा था—हल्का-सा, धोखे से अदृश्य, पर धीरे-धीरे हृदय के कक्षों को भरता हुआ।

भगवान शंकर, जिनकी दृष्टि त्रिकाल को एक क्षण में देख लेती है, इस धुएँ को भाँप चुके थे। वे जानते थे—अहंकार साधक का सबसे बड़ा शत्रु है। वह संन्यासी को घर से बाँध देता है, योगी को भटकाव में डाल देता है, और ब्रह्मज्ञानी को अज्ञान का दास बना देता है। इसलिए शंकर के मन में करुणा उभर आई—वह करुणा जो किसी साधक को पतन से बचाने के लिए ईश्वरीय मार्ग बनाती है।

वे नारद के पास आए, उनके सामने बैठकर अत्यंत विनम्र स्वर में बोले—

"हे मुनि, जिस कथा का तुमने स्मरण किया है, उसे प्रभु श्रीहरि के सम्मुख मत कहना।

काम-चरित, उलट-पुलट बातें वह मार्ग तुम्हें मदद नहीं करेगा।

यदि कभी ऐसा विषय उठे,
तो सौम्यता से प्रसंग बदल देना।"

इतना स्पष्ट, इतना स्नेह से भरा उपदेश किसी और को मिल जाता, तो वह माथे पर धारण कर लेता। पर नारद के हृदय में तब तक अहंकार का छोटा-सा सर्प डंक मार चुका था। उसे यह सरल चेतावनी भी ईर्ष्या जैसी प्रतीत हुई। उनकी बुद्धि भ्रमित होने लगी—

"क्या महादेव को भय है?
क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि संसार मुझे परमयोगी कहने लगे और उनकी महिमा कुछ दब जाए?
क्या इसलिए रोक रहे हैं?"

उनके कदम कैलाश से निकल पड़े, पर भीतर की कड़वाहट साथ ही चलती रही।

"पूछकर तो हमने समाधि नहीं लगाई।
बैकुण्ठ भी कौन अनुमति लेकर जाता है?"

इन विकृत विचारों में उलझे हुए नारद जैसे ही श्रीहरि के धाम पहुँचे, वहाँ का दृश्य बदल सा गया। विष्णुलोक का सौंदर्य स्वाभाविक ही मन मोह लेता था। स्वयं भगवान विष्णु ने दूर से ही नारद को देख लिया। वे उठकर आगे आए, देवी लक्ष्मी भी

साथ थीं। दोनों ने प्रसन्नता से देवर्षि का स्वागत किया।

उनके स्वागत का सौम्य वैभव देखकर नारद का हृदय भीतर तक पिघल गया।

"हे मुनिवर! बहुत दिनों बाद आपकी कृपा प्राप्त हुई!"

भगवान विष्णु का यह वचन जैसे फाहे की तरह उनके भीतर उतरा—कोमल, पर गहरा।

अहंकार की धूल और जम गई—

"देखा, प्रभु मेरे पराक्रम की कथा सुनने को उत्सुक हैं।
शंकर नाहक ही रोक रहे थे।"

और इसी भ्रम में, इसी दुर्भाग्यपूर्ण क्षण में, नारद ने वही गलती कर दी जिसके लिए शंकर उन्हें रोकना चाहते थे—

वे राम-चरित के स्थान पर काम-चरित का वर्णन करने लगे।

श्रीहरि बाहर से शांत बैठे रहे—वाणी मधुर, स्वर स्थिर, पर भीतर एक विषाद का बादल उठ रहा था।

उन्होंने केवल इतना कहा—

"हे मुनिराज, आपके स्मरण से मोह, मान, मद—सब मिट जाते हैं।
आप ब्रह्मचर्य-व्रती हैं।
आप पर कामदेव का प्रभाव?
सोचा भी नहीं जा सकता।"

यह प्रशंसा नहीं थी—यह चेतावनी का संकेत था।

पर नारद इसे समझ न सके।

उल्टा, यह मीठे शब्द उनके भीतर अहंकार को और सींचने लगे—

"देखा शंकरजी!
अनावश्यक रोका।
यहाँ तो मेरी कथा प्रिय लगी।"

अहंकार अब अंकुर नहीं रहा—वह वृक्ष बनने लगा था।

मुनि के शब्दों में विनय कम, स्वामित्व अधिक था।

श्रीहरि सब समझ रहे थे।

उनके मन में करुणा आई—

"यदि अभी इन्हें न रोका गया,
तो यह गर्व इनका महान पतन कर देगा।
सेवक का कल्याण करना ही हमारा धर्म है।"

और तत्काल उनके भीतर एक दिव्य योजना जन्म ले चुकी थी—

एक लीला, एक खेल, एक परीक्षा
जो नारद के अहंकार को तोड़ेगी,
कर्मफल का दर्पण दिखाएगी,
और उन्हें पुनः साधक के मार्ग पर स्थिर कर देगी।

मंच तैयार था—

नारद-मोह प्रसंग की अमर कथा को घटित करने का समय निकट आ चुका था।

इस कथा की शुरुआत अहंकार से हुई थी—

पर इसका अंत जागृति, ज्ञान और विनम्रता के पुनर्जन्म में होना था।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

कच्छ और सौराष्ट्र के लिए नए निवेश और औद्योगिक अवसरों के द्वार खोलेगा आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस

- कच्छ और सौराष्ट्र में तेज़ी से उभरते औद्योगिक एवं निवेश अवसर
- मोरबी, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, द्वारका और भावनगर पश्चिमी गुजरात के प्रमुख ग्रोथ हब
- द्वितीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसः 8–9 जनवरी 2026 को राजकोट में

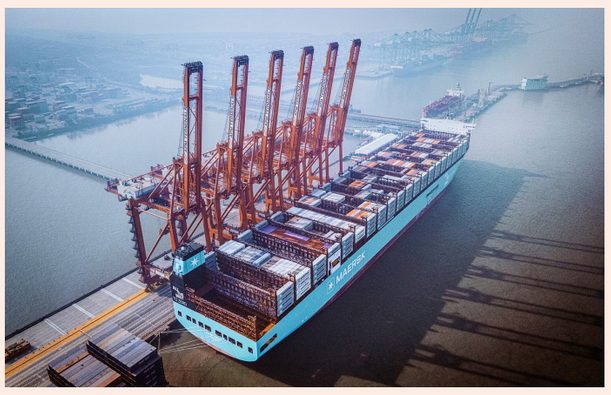

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात सरकार कच्छ और सौराष्ट्र के समग्र विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से द्वितीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। यह सम्मेलन इन दोनों क्षेत्रों में उभर रहे औद्योगिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवसरों को सामने लाने का एक महत्वपूर्ण मंच होगा। साथ ही, यह पश्चिमी गुजरात में तेजी से बढ़ते निवेश, नए अवसरों और समावेशी विकास की गति को भी रेखांकित करेगा।

क्षेत्रीय विकास के प्रमुख क्षेत्रों पर रहेगा विशेष फोकस

सम्मेलन में सेरामिक्स, इंजीनियरिंग, पोर्ट और लॉजिस्टिक्स, मत्स्य उद्योग, पेट्रोकेमिकल्स, एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग, खनिज, ग्रीन एनर्जी, कौशल विकास, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, पर्यटन और संस्कृति जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष चर्चाएं होंगी। रणनीतिक साझेदारियों, नीतिगत प्रोत्साहनों और निवेशकों की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से यह आयोजन पश्चिमी पट्टी में सतत् औद्योगिक विस्तार और संतुलित विकास को गति देने का उद्देश्य रखता है।

कच्छ से मोरबी और जामनगर तक: पश्चिमी गुजरात में उभरते नए निवेश केंद्र

कच्छ, भारत का सबसे बड़ा जिला, विकसित अवसंरचना, मजबूत बंदरगाह कनेक्टिविटी और विस्तार पाते औद्योगिक गलियारों के कारण आज वैश्विक व्यापार का प्रमुख केंद्र बन चुका है। कांडला और मुंद्रा जैसे देश के महत्त्वपूर्ण पोर्ट इसकी आर्थिक क्षमता को और मजबूती देते हैं। पशुपालन, विविध पर्यटन स्थलों और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों ने कच्छ को पेट्रोकेमिकल्स, 32 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और एग्रो प्रोसेसिंग के लिए अत्यंत आकर्षक निवेश गंतव्य बना दिया है।

मोरबी, जिसे देशभर में सिरेमिक कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, यह 900 से अधिक विनिर्माण इकाइयों के माध्यम से सिरेमिक उद्योग में गुजरात की नेतृत्वकारी भूमिका को स्थापित करता है। यह जिला घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में उल्लेखनीय योगदान देता है।

जामनगर, अपनी सशक्त औद्योगिक पहचान के साथ ब्रास सिटी ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ 15,000 से अधिक इकाइयाँ पीतल के महत्वपूर्ण उत्पादों का निर्माण करती हैं। आम, अमरूद और अनार जैसे उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के उत्पादन ने इसे एग्रो-आधारित उद्योगों का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया है। जामनगर में स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी इसकी वैश्विक औद्योगिक क्षमता को और बढ़ाती है।

राजकोट से तटीय जिलों तक: उद्योग, संस्कृति और व्यापार का मजबूत संगम

राजकोट, गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा जिला, देश के मशीन टूल्स और विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी है। MSME विकास, नवीन उद्यमिता और बांधणी-अजरख जैसी पारंपरिक कलाओं ने इसे औद्योगिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बनाया है।

पोरबंदर, महात्मा गांधी की जन्मभूमि, मत्स्य उद्योग, मिनरल प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प तथा देश के सबसे बड़े कॉस्टिक सोडा प्लांट के कारण औद्योगिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सौराष्ट्र केमिकल्स जैसी संस्थाएँ इस क्षेत्र के औद्योगिक तंत्र को मजबूती देती हैं। देवभूमि द्वारका, भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी पावन भूमि होने के साथ-साथ औद्योगिक रूप से भी उल्लेखनीय है। मिथापुर स्थित टाटा केमिकल्स का संयंत्र देश के प्रमुख सोडा ऐश उत्पादकों में शामिल है, जबकि ओखा बंदरगाह मछली उत्पादों, खनिजों और नमक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निर्णायक भूमिका निभाता है।

भावनगर, प्याज उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र होने के अलावा अलंग में स्थित विश्व के सबसे बड़े शिप-ब्रेकिंग यार्ड के कारण वैश्विक समुद्री उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बोटाद एक उभरता हुआ औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है। सुरेंद्रनगर, कपास, सौंफ और नमक उत्पादन में अग्रणी होने के साथ-साथ बंधनी और टांगलिया बुनाई की समृद्ध परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध है।

जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में कृषि और एग्रो-प्रोसेसिंग उद्योगों के साथ-साथ गिर राष्ट्रीय उद्यान और गिरनार पर्वत जैसी पर्यटन संपदाएँ इन्हें इको-टूरिज़्म और फूड प्रोसेसिंग के नए अवसरों से जोड़ती हैं। अमरेली, जहां देश का पहला निजी क्षेत्र का पिपावाव पोर्ट स्थित है, यह थोक व कंटेनर कार्गो के लिए प्रमुख समुद्री द्वार है। एग्रो और फूड प्रोसेसिंग तथा सीमेंट उद्योग ने अमरेली को सौराष्ट्र की औद्योगिक विविधता में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है।

8 और 9 जनवरी 2026 को राजकोट में आयोजित होगा द्वितीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस

राजकोट में आयोजित होने वाली आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस गुजरात सरकार की क्षेत्रीय प्रगति को अगले चरण में ले जाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सतत् औद्योगिक इकोसिस्टम, कौशल विकास और नवाचार पर विशेष फोकस के साथ कच्छ और सौराष्ट्र "विकसित गुजरात-विकसित भारत @2047" की परिकल्पना को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं।

पश्चिम रेलवे ने दर्ज किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ टिकट जांच प्रदर्शन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे ने अप्रैल से अक्टूबर 2025 की अवधि के दौरान टिकट जांच के क्षेत्र में अपना अब तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन प्राप्त किया है। इस दौरान लगभग 19 लाख बिना टिकट एवं अनियमित यात्रियों का पता लगाते हुए 121.67 करोड़ की राजस्व-राशि अर्जित की गई। इसमे अनबुक्ड लगेज के प्रकरण भी समाविष्ट हैं। यह उपलब्धि गत वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त 80.56 करोड़ की आय की तुलना में 51% की महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित करती है तथा यह रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 14% अधिक है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे ने अक्टूबर 2025 में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 24 करोड़ से अधिक की आय अर्जित की है, जो इस अवधि का दूसरा सर्वोत्तम मासिक रिकॉर्ड है। पश्चिम रेलवे का सर्वश्रेष्ठ मासिक रिकॉर्ड मई 2022 में स्थापित हुआ था, जब लगभग 26 करोड़ की आय प्राप्त हुई थी।

उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद मंडल ने अक्टूबर 2025 में 50 हजार प्रकरणों का संज्ञान लेकर 4 करोड़ से अधिक की राशि वसूल कर अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ टिकट जांच प्रदर्शन दर्ज किया। इसी क्रम में, मुख्यालय की फ्लाइंग स्क्वॉड ने भी अक्टूबर 2025 में 2.20 करोड़ का उत्कृष्ट राजस्व अर्जित करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ मासिक रिकॉर्ड स्थापित किया, जो मई 2022 में प्राप्त 2 करोड़ के पूर्ववर्ती रिकॉर्ड से अधिक है।

अक्टूबर 2025 के दौरान पश्चिम रेलवे ने कई दैनिक राजस्व उपलब्धियों के नए रिकॉर्ड भी स्थापित किए। पश्चिम रेलवे द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को लगभग 1.40 करोड़ की आय अर्जित की गई। इसी प्रकार 18 अक्टूबर 2025 को अहमदाबाद मंडल ने 38 लाख से अधिक, तथा रतलाम मंडल ने लगभग 16 लाख का राजस्व प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, 19 अक्टूबर 2025 को मुख्यालय की फ्लाइंग स्क्वॉड ने लगभग 16.30 लाख की आय दर्ज की।

ये उपलब्धियां पश्चिम रेलवे द्वारा टिकट रहित एवं अनियमित यात्रा पर अंकुश लगाने, यात्री अनुशासन को प्रोत्साहित करने हेतु संचालित व्यापक टिकट जांच अभियानों की प्रभावशीलता को दर्शाती हैं।

महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे की अहमदाबाद एवं वडोदरा क्षेत्राधिकार के माननीय सांसदों के साथ बैठक का आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय एवं संवाद को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत 21 नवम्बर 2025 को अहमदाबाद एवं वडोदरा मंडलों के क्षेत्राधिकार में आने वाले माननीय सांसदों के साथ महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे श्री विवेक कुमार गुप्ता की एक बैठक का आयोजन अहमदाबाद स्थित सर्किट हाउस में किया जा रहा है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों मंडलों में जारी यात्री सुविधाओं के उन्नयन, चल रही एवं प्रस्तावित परियोजनाओं, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास तथा जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर सार्थक संवाद स्थापित करना है। बैठक में अहमदाबाद एवं वडोदरा मंडलों में प्रगति पर विभिन्न नवीन यात्री सुविधाओं तथा विकासात्मक उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। इस दौरान प्रजेंटेशन के माध्यम से अहमदाबाद मंडल पर दिवाली एवं छठ पूजा के दौरान किए गए उत्कृष्ट क्राउड मैनेजमेंट प्रयासों, मंडल में प्रगति पर विभिन्न रेल परियोजनाओं—जैसे नई रेल लाइनों, नई ट्रेन सेवाओं, मेजर रिडेवलपमेंट स्टेशनों (भुज, अहमदाबाद, साबरमती) तथा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए जा रहे अन्य 16 स्टेशनों की प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही रेल सुविधाओं, परियोजनाओं, ट्रेनों के नए ठहराव, ट्रेन विस्तार, फेरे बढ़ाने तथा अन्य ढांचागत आवश्यकताओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी और जनप्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

इस बैठक में माननीय सांसदों में श्री हसमुखभाई पटेल (अहमदाबाद पूर्व), श्री दिनेशभाई मकवाना (अहमदाबाद पश्चिम), श्रीमती शोभनाबेन बारैया (साबरकांठा), श्री भरत सिंहजी डाभी (पाटन), श्री मितेशभाई पटेल (आणंद), श्री जशुभाई राठवा (छोटा उदयपुर), श्रीमती अनिता चौहान (रतलाम), श्री नरहरि अमीन (राज्यसभा) तथा श्री मयंकभाई नायक (राज्यसभा) उपस्थित रहेंगे।

रेलवे प्रशासन की ओर से महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे श्री विवेक कुमार गुप्ता, मंडल रेल प्रबंधक अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश, मंडल रेल प्रबंधक वडोदरा श्री राजू भडके, पश्चिम रेलवे मुख्यालय से आए प्रमुख मुख्य रेल अधिकारी, RLDA तथा दोनों मंडलों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहेंगे। यह पहल जनप्रतिनिधियों के साथ सहभागिता व सहयोग को बढ़ाकर रेल सुविधाओं के उन्नयन, यात्री सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करेगी।

रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ट्रेन में औचक टिकट जाँच, 161 बिना टिकट यात्रिओं से जुर्माना स्वरुप 50 हज़ार से अधिक की राशि वसूल

(जीएनएस)। वडोदरा मंडल अपने सम्माननीय यात्रिओं से वैध टिकट के साथ यात्रा करने की अपील करता है और बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर विभिन्न अभियान चलाता है। मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा अहमदाबाद से एकतानगर जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में हाल ही में रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में औचक टिकट जाँच रखी गयी, जिसके अंतर्गत 161 यात्रिओं को बिना टिकट पाया गया और उनसे जुर्माना स्वरुप 50 हज़ार से अधिक की राशि वसूल की गयी, जो अब तक की रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जाँच में सबसे अधिक आय है ।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 19 नवंबर, 2025 को अहमदाबाद से एकतानगर जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में यात्रिओं द्वारा अनियमित यानि बिना टिकट यात्रा को हतोत्साहित करने के लिए वडोदरा मंडल के वाणिज्य बिभाग द्वारा रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में औचक टिकट जाँच रखी गयी। टिकट जाँच दल में वाणिज्य विभाग के मुख्य टिकट इंस्पेक्टर श्री पी के झा, श्री रोशन लाल, श्री एम एस चौहान एवं उप मुख्य टिकट इंस्पेक्टर श्री तेजकरन एवं मुख्य टिकट कलेक्टर श्री ए के सिंह ने भाग लिया और यात्रिओं द्वारा बिना टिकट यात्रा के मामले पकड़े। इस औचक निरीक्षण में 161 यात्रिओं को बिना टिकट पाया गया और उनसे जुर्माना स्वरुप 50 हज़ार से अधिक की राशि वसूल की गयी, जो अब तक की रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जाँच में सबसे अधिक आय है ।

ये उपलब्धियाँ पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में गहन टिकट जाँच अभियानों के माध्यम से बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने और यात्री अनुशासन को बढ़ावा देने के वडोदरा मंडल के निरंतर प्रयासों को दर्शाती हैं।

अजमेर मण्डल में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेन प्रभावित रहेगी

(जीएनएस)। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मण्डल के मारवाड़ जं.-आउवा स्टेशनों के बीच स्थित ब्रिज नं. 590 किमी 437/4-5 पर आरसीसी बॉक्स लॉन्चिंग हेतु ब्लॉक लिए जाने के कारण कुछ ट्रेन प्रभावित रहेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

निरस्त ट्रेन

23 नवंबर 2025 को जोधपुर से चलने वाली ट्रेन संख्या 14821 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

24 नवंबर 2025 को साबरमती से चलने वाली ट्रेन संख्या 14822 साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

रेगुलेट ट्रेन

22 नवंबर 2025 की ट्रेन संख्या 14701 श्री गंगानगर-बांद्रा टर्मिनस अरावली एक्सप्रेस अजमेर-मारवाड़ के बीच 01.00 घंटा देरी से चलेगी।

23 नवंबर 2025 की ट्रेन संख्या 14822 साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस पालनपुर-मारवाड़ के बीच 25 मिनट देरी से चलेगी।

ट्रेनों के ठहराव, संरचना, मार्ग और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

कुर्रम में खून की बारिशः दो मुठभेड़ों में 23 विद्रोही ढेर, पाकिस्तान सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी

(जीएनएस)। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में एक बार फिर गोलियों की गूँज सुनाई दी। कुर्रम जिले की पहाड़ियों और जंगलों में बुधवार की रात से गुरुवार तक चले सुरक्षा अभियानों ने पूरे इलाके को दहला दिया। पाकिस्तान सेना ने घोषणा की है कि दो अलग-अलग मुठभेड़ों में कुल 23 विद्रोही लड़ाके मारे गए, जिनका संबंध कुख्यात संगठन "फितना अल ख्वारिज" से बताया जा रहा है।

घटनाओं की शुरुआत उस समय हुई जब सेना को कुर्रम के एक दुर्गम इलाके में विद्रोहियों की गतिविधियों के बारे में पुख्ता सूचना मिली। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने बताया कि सेना ने तत्काल ऑपरेशन छेड़ा। घेराबंदी के दौरान विद्रोहियों ने तेज़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभाला। इस भीषण मुठभेड़ में 12 विद्रोही मौके पर ही ढेर हो गए।

लेकिन खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसी इलाके से कुछ ही दूरी पर छिपे विद्रोहियों के दूसरे समूह की जानकारी मिलते ही सेना ने दूसरा अभियान शुरू किया। यह अभियान और भी अधिक चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा है। सुरक्षाबलों ने इस समूह को भी चारों तरफ से घेरकर ज़मीन और पहाड़ी क्षेत्रों में दबाव बढ़ाया। दूसरी मुठभेड़ में 11 और विद्रोही मार गिराए गए।

आईएसपीआर के अनुसार, यह अभियान केवल विद्रोहियों के सफाए भर का प्रयास नहीं है, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को नष्ट करने का प्रयास है जो लंबे समय से क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा था। सेना ने बताया कि इलाके में और भी विद्रोहियों के छिपे होने की आशंका है, जिसके लिए वृहद तलाशी अभियान लगातार जारी है। पहाड़ियों, जंगलों और आबादी रहित पट्टियों में सुरक्षाबल चप्पा-चप्पा खंगाल रहे हैं। कुर्रम जिला लंबे समय से आतंकी और उग्रवादी गतिविधियों का अड्डा माना जाता रहा है। यहां स्थित भौगोलिक संरचनाएँ—पहाड़ी घाटियाँ, घने जंगल और सीमावर्ती रास्ते—विद्रोहियों को छिपने, regroup करने और हमले की योजना बनाने में सहजता प्रदान करते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान सेना इस पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है।

स्थानीय लोगों के लिए पिछले दो दिनों के हालात भयावह रहे। गोलियों की तड़तड़ाहट, हेलीकॉप्टरों की उड़ानें और लगातार चल रहे सुरक्षा अभियानों ने वातावरण को तनावपूर्ण बना दिया है। हालांकि सेना का दावा है कि नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि 23 विद्रोही लड़ाकों का मारा जाना सेना की बड़ी सफलता है, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। "फितना अल ख्वारिज" जैसे संगठनों की जड़ें गहरी हैं और इनके खिलाफ चल रहा अभियान संभवतः और भी कड़ा होने वाला है।

ट्रंप ने बदली आप्रवासन बहस की दिशा: एच-1बी को अमेरिका की तकनीकी रीढ़ बताया

(जीएनएस)। वाशिंगटन की हवा इन दिनों असामान्य रूप से गर्म है—राजनीतिक और तकनीकी दोनों अर्थों में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अक्सर अपने 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' समर्थकों की उम्मीदों के केंद्र बिंदु रहे हैं, इस बार उसी समर्थन आधार के भीतर एक नई बहस खड़ी कर बैठे हैं। अमेरिकी-सऊदी निवेश मंच में उन्होंने जिस स्पष्टता के साथ एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम को अमेरिका की तकनीकी जरूरतों का आधार बताया, उससे न केवल उनके आलोचक चौंक गए, बल्कि उनके अपने समर्थक भी असहज दिखाई दिए।

ट्रंप ने मंच से कहा कि अमेरिका की विशाल तकनीकी महत्वाकांक्षाओं को केवल स्थानीय बेरोजगारों से पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने एरिज़ोना में प्रस्तावित अरबों डॉलर की चिप फ़ैक्ट्रियों का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी परियोजनाएँ केवल उन विशेषज्ञ हाथों से चल सकती हैं, जो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से अमेरिका तक आते हैं। उन्होंने इसे ही "असली मागा" बताया और कहा कि वैश्विक प्रतिभा को अमेरिका में काम करने देना, देश को मज़बूत करने का सबसे व्यावहारिक तरीका है।

राष्ट्रपति ने कहा कि विदेशी विशेषज्ञ सिर्फ मशीनें नहीं चलाते, वे ज्ञान भी लाते हैं—ऐसा ज्ञान जो आने वाले वर्षों में अमेरिकी कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर देश को तकनीकी प्रतिस्पर्धा में आगे रखेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि प्रशिक्षण के बाद कई विशेषज्ञ वापस अपने देशों चले जाते हैं, लेकिन उनके छोड़े कौशल और कामकाजी संस्कृति का लाभ वर्षों तक अमेरिका को मिलता रहता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के भीतर तकनीकी प्रतिभा की कमी स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है। कई हाई-टेक कंपनियाँ लंबे समय से कहती रही हैं कि खास क्षेत्रों—जैसे सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपरकम्प्यूटिंग, सैटेलाइट टेक—में घरेलू विशेषज्ञों की संख्या जरूरत के मुकाबले बेहद कम है।

ट्रंप ने इस स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि अगर अमेरिका को तकनीकी युद्ध में जीतना है, तो उसे वैश्विक विशेषज्ञों की मदद लेने में हिचकना नहीं चाहिए।

लेकिन इस भावनात्मक और व्यावहारिक तर्क के पीछे राजनीतिक झंझावात भी कम नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ही लॉरा लूमर और बेनी जॉनसन जैसे नाम एच-1बी कार्यक्रम के सबसे बड़े आलोचक हैं। उनका आरोप है कि यह कार्यक्रम अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियों को खतरे में डालता है। वे इसे "अमेरिका फर्स्ट में सेंध" बताते हैं। इन आलोचनाओं को ट्रंप पहले भी खारिज कर चुके हैं और हाल ही में फॉक्स न्यूज़ पर दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया था कि अमेरिका अभी भी "दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रतिभा संकट" से गुजर रहा है। इस पूरी बहस के बीच एक नई हलचल सितंबर में तब पैदा हुई जब ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीज़ा के लिए एक लाख डॉलर तक की फीस का प्रस्ताव रख दिया। इस निर्णय से राजनीतिक माहौल और उद्योग जगत के बीच तनाव और बढ़ गया। जहाँ रिपब्लिकन पार्टी का एक तबका इसे सख़्त आप्रवासन नीति का आवश्यक हिस्सा मानता है, वहीं तकनीकी कंपनियाँ चेतावनी दे रही हैं कि अगर विशेषज्ञों की आवाजाही रोकी गई, तो अमेरिका की तकनीकी क्षमता और वैश्विक नेतृत्व पर सीधा असर पड़ेगा। मंच से उतरते समय भी ट्रंप ने वही बात दोहराई—अमेरिका को अगर आगे बढ़ना है तो उसे अपने दरवाज़े दुनिया के सामने पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए। उनके शब्दों में, "तकनीक की दुनिया सीमाओं से नहीं चलती। अगर अमेरिका अपनी सीमाएँ बहुत कसकर बंद कर लेगा, तो भविष्य किसी और के हाथ चला जाएगा।" अमेरिका की राजनीति में यह बयान आने वाले दिनों में नई बहस को जन्म देगा, लेकिन एक बात अब साफ है—एच-1बी वीज़ा पर लड़ाई केवल आप्रवासन की नहीं, बल्कि अमेरिका के भविष्य की है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने टेक्नोलॉजी के उपयोग से ऑनलाइन जन शिकायत निवारण के कार्यक्रम 'स्वागत' में उपस्थित रहकर शिकायतों के निवारण का मार्गदर्शन दिया

- मुख्यमंत्री ने किसानों सहित सभी लोगों की समस्याओं का जमीन पर जाकर तथा गहराई से समझकर तत्काल निवारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए
- मुख्यमंत्री ने तहसील और जिला 'स्वागत' के निर्णयों के स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन और गहन निगरानी के लिए जिला कलेक्टरों को दिए निर्देश
- राज्य 'स्वागत' में 70 से अधिक नागरिकों ने अपनी शिकायतें प्रस्तुत कीं, जिला 'स्वागत' की 1156 शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही जिला स्तर पर की गई

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को गांधीनगर में आयोजित नवंबर महीने के राज्य स्तरीय 'स्वागत' (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम में प्रस्तुत शिकायतों और समस्याओं के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को साफ तौर पर कहा कि लोगों की समस्याओं और शिकायतों को गहराई से समझते हुए तथा जमीन पर जाकर उनका शीघ्र निवारण करना आवश्यक है।

बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2003 में शुरू किया गया राज्य 'स्वागत' कार्यक्रम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सरकार के समक्ष पहुंचाने के साथ ही समस्या के निवारण से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के नागरिकों की समस्याओं को हमेशा प्राथमिकता देकर उनके त्वरित निवारण के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, इसकी मिसाल नवंबर महीने के राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम में देखने को मिली।

इस राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम में 70 से अधिक नागरिक अपनी समस्याएं प्रस्तुत करने के लिए आए थे, जिनमें से 4 आवेदकों की समस्याओं को मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर सुना। जबकि शेष समस्याओं को मुख्यमंत्री जनसंपर्क इकाई के अधिकारियों ने सुना और कार्रवाई के लिए संबद्ध विभागों तथा जिला स्तर के अधिकारियों को भेजा। राज्य सरकार द्वारा आयोजित नवंबर महीने के जिला 'स्वागत' के तहत प्राप्त 1156 शिकायतों की निराकरण कार्यवाही जिला स्तर पर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्तर पर तहसील और जिला 'स्वागत' की शिकायतों के संबंध में लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन और उनकी गहन निगरानी के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने जिन तहसीलों और जिलों में लंबित शिकायतों की संख्या अधिक है, ऐसे जिलों में शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने के दिशानिर्देश भी दिए।

पोरबंदर जिले के दो गांवों के किसानों ने सुखभादर नदी पर पुल बनाने की लंबे समय से लंबित मांग को लेकर राज्य 'स्वागत' में मुख्यमंत्री के समक्ष गुहार लगाई। इस पर मुख्यमंत्री ने उन किसानों के प्रति संवेदना दर्शाते हुए इस पुल को मंजूरी देने के लिए सड़क एवं भवन विभाग के सचिव को त्वरित कार्यवाही का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने पोरबंदर के ही एक अन्य अभ्यावेदक को तत्काल उसके भूखंड के निर्धारित क्षेत्रफल के साथ प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान करने के लिए पोरबंदर कलेक्टर आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद जिला कलेक्टर से कहा कि वे धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) के लिए आरक्षित भूमि के चलते धोलेरा तहसील के एक अभ्यावेदक की खेती की जमीन में हुई क्षति-नुकसान के कारण सात-बारह (राजस्व दस्तावेज) में दर्ज नोट को हटाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे इस बात का विशेष ख्याल रखें कि हाल में हुई असाधारण बेमौसम बारिश के चलते किसानों को हुए नुकसान को लेकर राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए कृषि पैकेज सहायता प्राप्त करने में किसी भी किसान को कोई दिक्कत ना हो।

नवंबर-2025 के इस राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) सर्वश्री धीरज पारेख और राकेश व्यास तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ सचिव एवं अधिकारी मौजूद रहे।

दिल्ली ब्लास्ट की खामोशी में छिपी नक़ाबपोश साजिश: आतंकियों के फोन में मिले जहरीले वीडियो, बम ट्रेनिंग और विदेशी कनेक्शन के चौंकाने वाले राज

(जीएनएस)। दिल्ली में 10 नवंबर की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में खड़ी एक i20 कार अचानक आग के गोले में बदल गई। धमाके ने न सिर्फ आसपास की दीवारों को झकझोर दिया बल्कि शहर की सांसें भी थाम दीं। शाम के 6 बजकर 52 मिनट पर हुआ यह विस्फोट आज़ादी के बाद दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया। मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है और 20 से अधिक घायल अस्पतालों में ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। वही कार चला रहा आतंकी डॉ. उमर भी उसी धमाके में मारा गया, लेकिन उसके पीछे खड़ी साजिश की जड़ें इतनी गहरी निकलीं कि जांच एजेंसियों के चेहरे भी हैरान रह गए। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल फोन ने ऐसी दुनिया के दरवाज़े खोल दिए जो आम नागरिक कल्पना भी नहीं कर सकते। पकड़े गए डॉक्टर—मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और इरफान—सबके फोन से डिलीट किए गए डेटा को तकनीकी टीम ने वापस निकाला। और फिर सामने आया वीडियो, ऑडियो और चैट का वो जाल जिसने पूरी साजिश की गहराई को उजागर कर दिया।

डॉ. मुजम्मिल के फोन में करीब 200 वीडियो मिले। इनमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाले वीडियो वे थे जिनमें जैश-ए-मोहम्मद और ISIS के आतंकी कमांडरों के जहरीले भाषण थे। मसूद अज़हर, असगर और जैश के कई शीर्ष कमांडरों की तकरीरें नफरत, हिंसा और कट्टरता से भरी हुई थीं। इसके अलावा 80 वीडियो ऐसे थे जो आतंकी ट्रेनिंग से जुड़े थे—बम कैसे बनाए जाते हैं, कौन सा केमिकल किस रिएक्शन में काम आता है, कैसे एक साधारण से उपकरण में विस्फोटक क्षमता पैदा की जाती है—यह सब बेहद विस्तार से मौजूद था।

फोन में मिली सामग्री से एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। साल 2022 में मुज़म्मिल और डॉक्टर उमर तुर्की पहुँचे थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक सीरियाई ISIS कमांडर से करवाई गई थी—यह मुलाकात जैश-ए-मोहम्मद के संकेत पर हुई थी। उसी कमांडर ने उन्हें बम बनाने की तकनीकी मदद दी थी। जिन वीडियो में बम मेकिंग दिख रही है, उनमें से कई तुर्की-सीरिया बॉर्डर के ISIS ट्रेनिंग कैंप से रिकॉर्ड किए गए थे। फोन में भारत के भीड़भाड़ वाले बाज़ारों, धार्मिक स्थलों, दिल्ली–UP–मुंबई के कई संवेदनशील इलाकों की रेकी वीडियो भी मिले हैं, जिन्हें देखकर साफ लगता है कि यह कोई एक दिन की योजना नहीं थी—यह कई महीनों के तैयारी का संगठित ब्लूप्रिंट था।

जांच में सामने आया कि यह पूरी टीम डॉक्टरों की थी—शिक्षित, तकनीकी ज्ञान रखने वाली, समाज में सम्मानित दिखने वाली—but पर्दे के पीछे प्रत्येक व्यक्ति कट्टर विचारों से प्रभावित होकर आतंकी संगठनों का मोहरा बन चुका था। यही बात सुरक्षा एजेंसियों को सबसे ज्यादा चिंतित कर रही है—अब आतंकवाद सिर्फ सरहद पार से नहीं, बल्कि शिक्षित समाज के भीतर से भी आकार ले रहा है।

ब्लास्ट के बाद देश भर में छापेमारियाँ की गईं। दो दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। उनकी चैट हिस्ट्री, एन्क्रिप्टेड कॉन्टैक्ट्स, और विदेशी नंबरों से हुई बातचीत ने इस नेटवर्क के फैले हुए पाँवों की झलक दी। दिल्ली से लेकर यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक—कई राज्यों में सक्रिय यह मॉड्यूल बड़े पैमाने पर हमलों की तैयारी कर रहा था।

आज भी जांच जारी है। कई फोन की फोरेंसिक जांच अभी अधूरी है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ की हर परत एक नई साजिश उजागर कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि उस जमीनी सच्चाई का आईना है कि आतंकी संगठन लगातार नए चेहरों, नई तकनीकों और नई रणनीतियों के साथ भारत को निशाना बना रहे हैं।

देश की राजधानी में हुआ यह धमाका सिर्फ एक विस्फोट नहीं था—यह चेतावनी थी कि डिजिटल आतंकवाद, विदेशी नेटवर्क और ज़हरीली विचारधाराओं का गठजोड़ अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है।

रांची की रात में छुपी बारूद की बड़ी कहानी : 5000 जिलेटिन स्टिक, 300 डेटोनेटर और पुलिस की उस तेज कार्रवाई का किस्सा जिसने एक खौफनाक साजिश को अंजाम से पहले ही तोड़ दिया

(जीएनएस)। दिल्ली के कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। राजधानी की सनसनी ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट मोड पर ला दिया है। इसी तनाव और सतर्कता के बीच झारखंड के रांची में बुधवार की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने साबित कर दिया कि कई बार खामोश गलियों में भी ऐसी आग सुलग रही होती है जिसे अगर समय पर रोक न लिया जाए तो एक शहर ही नहीं, पूरा प्रदेश दहल सकता है।

ओरमांझी थाना क्षेत्र के पिस्का गांव में एक साधारण-सा मकान था—एल्वेस्टर लगा, दो कमरे, बाहर टूटी बाउंड्री और भीतर सन्नाटा। किसी को क्या पता कि इस सन्नाटे में हजारों किलोमीटर दूर की कोई आवाज गूंज रही है, कोई अवैध कारोबार खामोश चालें चल रहा है और किसी बड़ी साजिश की जड़ें इसी घर की दीवारों के भीतर फैली हुई हैं। लेकिन एसएसपी को मिली एक छोटी-सी गुप्त सूचना ने इस मकान का चेहरा ही बदल दिया।

सूचना थी—"विस्फोटक का बड़ा जखीरा छिपाकर रखा गया है।"

बस, फिर पुलिस की तेजी उसी पल शुरू हो गई।

रांची एसपी ग्रामीण के आदेश पर सिल्ली डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। रात की नमी और गांव की गलियों की खामोशी के बीच जब यह टीम पिस्का गांव के उस मकान तक पहुंची, तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि अंदर क्या मिलेगा। दरवाज़ा खुलते ही जिस बदबूदार प्लास्टिक बैग ने सबका ध्यान खींचा, वही बाद में पूरे मामले की जड़ निकला। तलाशी बढ़ी, मकान की धूल भरी कोठरियों को खोला गया और कागज़ के 25 गत्ते के कार्टून पुलिस वालों की हथेलियों से गुजरते ही भारी हो गए।

कार्टून खोले गए और भीतर चमकते हुए पीले रंग के सिलिंडरनुमा जिलेटिन स्टिक दिखाई दीं। एक के बाद एक कार्टून खुले और संख्या बढ़ती चली गई—5000 जिलेटिन स्टिक। इसके पास ही बंडल में लाल और पीले रंग के तार मिले, और उनके भीतर छिपी थी इस जखीरे की सबसे खतरनाक नस—300 डेटोनेटर।

हर बंडल में 15 डेटोनेटर।

हर डेटोनेटर, एक विस्फोट का जन्मदाता।

पुलिस के दस्ताने पहनकर इन्हें उठाने की धीमी और सावधानी भरी हरकतें जैसे पूरे कमरे का माहौल जमा रही थीं। जब्त होने वाले हर पीस के साथ पुलिस को इस गहरी साजिश का दायरा और साफ होता जा रहा था। कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो गया कि यह सामग्री अवैध माइनिंग के काम में इस्तेमाल की जानी थी—जहां धमाका सिर्फ जमीन नहीं फाड़ता, बल्कि कानून और इंसानियत को भी चीर देता है।

पूछताछ के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि यह मकान झगरू बेदिया का है—गांव का ही निवासी, लेकिन लंबे समय से अवैध कारोबार में लिप्त होने की खबरें पहले भी आती रही थीं। पुलिस अब उसी की तलाश में दबिश दे रही है। थाने में मामला दर्ज हो चुका है और गिरफ्तारी की बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है।

लेकिन यह सिर्फ विस्फोटक बरामद होने की कहानी नहीं है। यह उस बढ़ते अपराध की कहानी है जिसे रोकने के लिए रांची पुलिस लगातार 'एंटी क्राइम चेकिंग अभियान' चला रही है। हाल के दिनों में 70 जगहों पर अड्डाबाजी करने वाले 183 लोगों को उठाकर हिदायत देनी पड़ी—"अगली बार पकड़े गए तो सीधे जेल।"

ये कार्रवाइयां बताती हैं कि रांची पुलिस अब सिर्फ अपराध रोकने में नहीं, बल्कि अपराध होने से पहले ही उसे दबाने की कोशिश में जुट गई है।

क्योंकि विस्फोटक जब बरामद होते हैं—तो सिर्फ बारूद नहीं पकड़ा जाता, बल्कि किसी बड़े हादसे की पूरी कहानी वहीं खत्म हो जाती है।

इंस्टा की चमक के पीछे छिपी अंधेरी दुनिया: 1.3 मिलियन फॉलोअर्स वाली कीर्ति पटेल अब वडोदरा जेल की कैदी नंबर में बदल गई

(जीएनएस)। गुजरात की सूरत पुलिस ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया जिसने सोशल मीडिया की चमकदार दुनिया और अपराध की अंधेरी गहराइयों के बीच की दूरी को एकदम साफ कर दिया। इंस्टाग्राम पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाली कीर्ति पटेल—जो अपने दबंग तेवर, ललकार भरे वीडियो, धमकी भरी भाषा और बेबाक अंदाज़ के कारण अक्सर सुर्खियों में रहती थीं—अब वडोदरा की सेंट्रल जेल में बंद हैं। वह चेहरे पर मेकअप और कैमरे की रोशनी में दिखने वाली सेल्फ-मेड इन्फ्लूएंसर नहीं बल्कि कई जिलों में दर्ज अपराधों वाली एक अभियुक्त बन चुकी हैं।

सूरत, गांधीनगर, पाटण और जूनागढ़—इन चार जिलों में उनके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। कीर्ति पटेल पर जबरन वसूली, लोगों को बदनाम करने, धमकियाँ देकर पैसे लेने और लगातार क्रिमिनल गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत उपस्थिति, उनके हर वीडियो पर लाखों लाइक और हजारों कमेंट, इन सबने उनके चारों ओर एक चमकीला कवच बना दिया था। ऐसा लगता था जैसे वह कानून से ऊपर चल रही हों, जैसे डिजिटल ताकत ने उन्हें वास्तविक दुनिया की सीमाओं से मुक्त कर दिया हो।

फिर भी, पुलिस की नज़रें कभी बंद नहीं होतीं। सूरत पुलिस ने पिछले दिनों फैसला किया कि सामान्य कानूनी प्रक्रिया कीर्ति पटेल जैसी लगातार अपराधों में लिप्त व्यक्ति को रोक पाने में सक्षम नहीं है। जमानत पर बाहर आने के बाद वह पहले जैसे ही धमकी भरे वीडियो डालती रहीं, गालियां देती रहीं, लोगों को डराती रहीं और अपने फॉलोअर्स के बीच एक गैंगस्टर-स्टाइल इमेज बनाए रखती रहीं। पुलिस का कहना है कि उनके वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं थे—वे कई लोगों में डर और खतरे का माहौल बना रहे थे।

यही कारण था कि पुलिस ने उनके खिलाफ PASA (Prevention of Anti Social Activities Act, 1985) लागू किया—एक ऐसा कानून जो केवल उन लोगों पर लागू किया जाता है जिनके कारण सार्वजनिक सुरक्षा बिगड़ने का गंभीर खतरा हो। PASA कोई साधारण कानून नहीं है। यह सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी व्यक्ति को उसके गृह जिले से दूर किसी अन्य जिले की जेल में बंद रख सके, ताकि वह अपने इलाके में प्रभाव न जमा सके और लोगों को धमकाकर फिर से अपराध की दुनिया न खड़ी कर सके। कीर्ति पटेल को अहमदाबाद से पकड़ा गया और तुरंत वडोदरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया—यह उसी कानून की पहली और सबसे सख्त कार्रवाई थी। PASA लागू होने का मतलब है कि आरोपी के लिए जमानत लगभग असंभव हो जाती है। अक्सर इसमें एक साल तक जेल में रहना पड़ता है क्योंकि यह कानून अपराध को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, न कि सिर्फ हुई घटना की सज़ा देने के लिए। यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जो बार-बार अपराध करते हैं, जमानत पर छूटकर फिर वही सब दोहराते हैं और जिनसे समाज को वास्तविक खतरा पैदा हो जाता है।

कीर्ति पटेल के लिए यह गिरफ़्तारी सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं है—यह उसकी दो दुनिया के टकराव की कहानी है। एक तरफ सोशल मीडिया की चमकदार दुनिया, ग्लैमर, लोकप्रियता, लाइक्स और रील्स की दुनिया थी; दूसरी तरफ कानून की सख्त, ठंडी और वास्तविक दुनिया, जहाँ फॉलोअर्स नहीं बल्कि केस डायरी चलते हैं, जहाँ लाइक्स नहीं बल्कि आपराधिक धाराएँ मायने रखती हैं, और जहाँ इमेज नहीं बल्कि अपराध की फाइलें फैसला सुनाती हैं।

लाखों फॉलोअर्स वाली यह डिजिटल स्टार अब वडोदरा जेल की बंद दीवारों के भीतर है, जहाँ कैमरा नहीं, सिर्फ सन्नाटा है। जहाँ कोई रील नहीं, सिर्फ हकीकत है। और यह हकीकत बताती है कि चाहे सोशल मीडिया कितना ही मजबूत क्यों न बना दे, कानून का हाथ आखिरकार सबसे मजबूत होता है।

नीतीश कुमार का दसवां शपथ दिवस: जातियों के गणित, राजनीतिक परिवारों की परछाइयाँ और गांधी मैदान में गूंजती सत्ता की नई प्रतिध्वनि

(जीएनएस)। पटना का गांधी मैदान उस सुबह कुछ अलग ही चमक लिए हुए था। हवा में राजनीति का ताप भी था और उम्मीदों की ठंडक भी। मंच पर नीतीश कुमार खड़े थे—दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे थे। उनके सामने हज़ारों की भीड़ थी और उनके पीछे वह अनुभव था जिसने बिहार की राजनीति को तीन दशकों तक संभाला और मोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आए, उनके हाथ में सफेद गमछा था, जिसे उन्होंने लहराया—और वह एक पल में बिहार की राजनीति की नई प्रतीक-छवि बन गया। भीड़ से निकली आवाजें, कैमरों की चमक, नेताओं के चेहरे और मंच का भार—सब एक क्षण में जैसे जम सा गया।

नीतीश कुमार के साथ 26 और चेहरों ने शपथ ली। मंच पर मंत्रियों की आवाजें एक साथ उठीं, इतनी कि किसी एक की आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं दी। शपथ ग्रहण के इतिहास में ऐसे क्षण कम ही आते हैं जब शब्दों से ज़्यादा दृश्यों का प्रभाव दर्ज हो। सामान्यतः हर मंत्री अकेले शपथ लेता है, शब्दों का वजन तौला जाता है, उच्चारण की त्रुटि पर टोक दिया जाता है, लेकिन आज समूह की गूंज में यह सब धुंधला था। यह दृश्य अपने आप में कहानी बयाँ कर रहा था—मंत्रिमंडल बड़ा है, वक्त कम है, और सत्ता जल्दी गति पकड़ना चाहती है।

नीतीश कुमार की टीम में कुल 27 मंत्री शामिल किए गए और इसमें एक पूरा सामाजिक मानचित्र छिपा हुआ है। राजपूतों से लेकर मल्लाहों तक, दलितों से लेकर पिछड़ों तक, यादवों से लेकर भूमिहारों तक—हर किसी को हिस्सेदारी दी गई है। राजपूत सबसे आगे, दलित दूसरे स्थान पर, फिर भूमिहार और कुशवाहा। यादव समुदाय की 14% आबादी को ध्यान में रखकर दो मंत्रियों को जगह दी गई। मुस्लिम मंत्री को भी शामिल किया गया। पूरा मंत्रिमंडल मानो बिहार की सामाजिक बुनावट को उसकी राजनीतिक

अभिव्यक्ति दे रहा था। जातियों का यह गणित बिहार की राजनीति की धड़कन है और नीतीश कुमार इस धड़कन को समझने में माहिर माने जाते हैं।

इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का गमछा लहराना पूरे समारोह का सबसे जीवंत क्षण बन गया। चुनावी रैलियों में उन्होंने इसी तरह गमछा लहराने की परंपरा शुरू की थी। आज पटना में, नीतीश कुमार की नई पारी में भी वही दृश्य दोहराया गया। भीड़ ने इसे उत्साह से स्वीकार किया। राजनीति में प्रतीकों का अर्थ अक्सर बहुत गहरा होता है और मोदी का यह इशारा बिहार में एक विशेष संदेश की तरह देखा गया।

पर आज की सबसे ज्यादा चर्चा में जो बातें रहीं, उनमें से एक थी परिवारवाद की कथाएँ। उपेंद्र कुशवाहा—एक तरफ़ खुद राज्यसभा में, दूसरी तरफ़ पत्नी विधायक, और अब बेटा बिना चुनाव लड़े मंत्री। यह दृश्य बिहार की राजनीति का वह आईना है जिसमें सत्ता की वंशानुगत परंपरा साफ दिखती है। जीतनराम मांझी की कहानी भी इसी आईने का प्रतिबिंब है—खुद केंद्र सरकार में मंत्री, बेटे संतोष सुमन राज्य मंत्री, बहू, समधन और दामाद—सभी बिहार की विधानसभा में चुनकर पहुँचे। लेकिन मंत्री अभी सिर्फ़ बेटे को बनाया गया है।

विपक्ष की नजरें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता और पूर्व सांसद शकुनी चौधरी पर भी टिकी रहती हैं। पूर्व सांसद दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह और जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी जिनकी बेटी लोकसभा सांसद हैं—वे सभी इसी बहस का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा लगता है बिहार की राजनीति एक ऐसे वृक्ष की तरह है जिसकी शाखाओं पर परिवारों की कई पीढ़ियाँ बैठी हैं। हर पीढ़ी सत्ता की अपनी कहानी जोड़ती है और हर कहानी, एक बहस भी जोड़ती है।

इन सबके बीच एक और दृश्य था जिसने सबका ध्यान खींचा—नीतीश कुमार के बेटे निशांत। वे राजनीति से हमेशा दूर ही रहे हैं, लेकिन आज मंच की दर्शक दीर्घा में बैठे अपने पिता को दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते देख रहे थे। उनमें वह चमक नहीं थी जो किसी राजनीतिक उत्तराधिकारी में दिखती है, न वह अधीरता जो अक्सर राजनीति की ओर आकर्षित होने वालों में दिखाई देती है। वे सिर्फ देख रहे थे—एक शांत स्वीकृति के साथ, जैसे कोई व्यक्ति जानता हो कि यह रास्ता उसका नहीं, उसके पिता का है।

शपथ ग्रहण समारोह 36 मिनट चला, लेकिन वह 36 मिनट बिहार की राजनीति के तीन दशक को अपने भीतर समेटे हुए था। जातियों का संतुलन, राजनीतिक परिवारों की मौजूदगी, प्रधानमंत्री की उपस्थिति, भीड़ की ऊर्जा, और नीतीश कुमार की स्थिर मुस्कान—सब मिलकर यह बता रहे थे कि बिहार में सत्ता भले ही बदलती रहे, पर उसकी लय वही रहती है जिसे नीतीश कुमार वर्षों से साधते आए हैं।

आज पटना के गांधी मैदान में सिर्फ़ शपथ नहीं ली गई—एक नई कथा की शुरुआत भी हुई। कौन जानता है यह कथा कितनी लंबी चलेगी, कौन इसे कैसे बदलेगा, और किस मोड़ पर इतिहास इसे अलग अर्थ देगा। लेकिन आज के दृश्य ने यह जरूर साफ़ कर दिया कि बिहार की राजनीति अपने हर अध्याय में जितनी जटिल होती है, उतनी ही दिलचस्प भी।

भावनगर के अंधेरे में दबी दास्तान: फॉरेस्ट अधिकारी के घर के पास से निकला तीन ज़िंदगियों का राज

(जीएनएस)। भावनगर जैसे शांत शहर में कभी-कभार ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं जो पूरे समाज को भीतर तक हिला देती हैं। सरकारी कॉलोनी की सड़कों पर फैली रोज़मर्रा की शांति के पीछे, एक ऐसा राज़ धीरे-धीरे पक रहा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। न किसी ने आवाज़ें सुनीं, न किसी ने चीखें, न किसी को कोई हरकत दिखी। सब कुछ सामान्य लगता रहा—जब तक कि मिट्टी के नीचे दबी सच्चाई ने सबका दिल दहला नहीं दिया।

शैलेश खंभला, सहायक वन संरक्षण अधिकारी—सरकार की वर्दी पहनने वाला वह व्यक्ति, जिसे ज़िम्मेदारी और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है—7 नवंबर को थाने में दाख़िल हुआ था। चेहरे पर न घबराहट, न बेचैनी। उसने पुलिस से कहा कि उसकी पत्नी नयना और दो बच्चे अचानक गायब हो गए हैं। बेटी सिर्फ 13 साल की थी और बेटा 9 का। उसने साधारण सी आवाज़ में गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाई और घर लौट गया। पुलिस ने पूरी प्रक्रियाएँ शुरू कीं—लोगों से पूछताछ, इलाके की तलाशी, मोबाइल लोकेशन की पड़ताल—लेकिन तीनों का कोई निशान नहीं मिला। दस दिन तक यह मामला सिर्फ एक लापता परिवार की कहानी लगा, लेकिन धीरे-धीरे इसमें एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको

अविश्वास में डाल दिया।

सरकारी क्वार्टरों के पास रहने वाले कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले उस इलाके में मिट्टी खोदी गई थी और अगले दिन उसे फिर से समतल कर दिया गया। सरकारी परिसर में ऐसी गतिविधि अक्सर विभाग द्वारा होती है, लेकिन इस बार किसी को किसी आधिकारिक काम के बारे में जानकारी नहीं थी। यह छोटी-सी जानकारी पुलिस के लिए बड़ा संकेत बन गई। तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय लोगों के बयान ने जांच को इसी दिशा में मोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक नितेश पांडे की देखरेख में सोमवार की सुबह टीम, मजिस्ट्रेट और फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ उस जगह पहुँची। हवा में तनाव घुल चुका था। जैसे-जैसे फावड़े मिट्टी को हटाते गए, जमीन की परतें सख़्ती से प्रतिरोध करती लगीं, मानो अपने भीतर छिपे राज़ को बाहर आने से रोक रही हों। कुछ फीट नीचे जाकर खुदाई की मिट्टी अचानक बदली हुई लगी—गीली, ताज़ा और अनजान। और फिर, कुछ ही देर में सबकी साँसें थम गईं।

पहला शव बाहर निकला। फिर दूसरा। और फिर तीसरा। तीनों एक साथ दबी हुई मिट्टी से बाहर आए—वही नयना, वही बच्चे, जिनके लिए शहर भर में तलाश चल रही थी। परिवार जैसे डूब गया। पुलिस टीम भी स्तब्ध रह गई। एक पल में यह मामला गुमशुदगी से उठकर एक भयावह त्रासदी बन चुका था।

जब परिजनों ने शव देखे, दर्द हवा में गूंजने लगा। सवाल सभी के मन में एक ही था—आख़िर ऐसा कौन कर सकता है? और कैसे?

लेकिन पुलिस की नज़रें एक ही दिशा में घूमकर ठहर रही थीं—शैलेश खंभला। वही व्यक्ति जिसने शिकायत दर्ज कराई थी। वही व्यक्ति जिसके घर के सामने ज़मीन खुदी थी। वही व्यक्ति जिसके हाव-भाव में कमी थी, लेकिन सवालों की गहराई का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। पूछताछ शुरू हुई तो उसके बयान समय-समय पर बदलने लगे। मोबाइल लोकेशन, गतिविधियाँ, घटनाओं के टाइमलाइन—बहुत कुछ मेल नहीं खा रहा था।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परिवार सामान्यतः सूरत में रहता था और छुट्टियों के चलते भावनगर आया हुआ था। सब खंभला के सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे। यही वह समय था जब कहीं कुछ फटा, कहीं कोई विवाद उठा, कहीं कोई तनाव चरम तक पहुँचा और उसे खत्म करने का रास्ता शायद सबसे क्रूर रूप में निकाला गया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, जो बताएगी कि मौत कैसे हुई—गला दबाया गया, मारपीट की गई, या कोई और तरीका अपनाया गया। लेकिन पुलिस के मुताबिक हत्या का अंदेशा अब पूरी तरह पक्का लग रहा है और शैलेश खंभला इसका मुख्य संदिग्ध है।

भावनगर की कॉलोनियों में आज खामोशी है। बच्चे खेलने बाहर नहीं निकले। लोग दरवाज़ों से बाहर सिर झुकाकर निकलते हुए सिर्फ एक ही बात सोच रहे हैं—कैसे एक पिता अपने ही बच्चों के लिए मौत का गड्ढा खोद सकता है? कैसे एक पति अपनी पत्नी को ऐसी अंधेर दुनिया में धकेल सकता है जहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था?

राजस्थान का रंग, संस्कृति की महक और 6000 महिलाओं का अपूर्व संगम: जब डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने हजारों रंगीन घाघरों के बीच थामा घूमर का लयबद्ध स्वर

(जीएनएस)। राजस्थान की धरती बुधवार को मानो अपनी प्राचीन आत्मा से फिर एक बार चमक उठी। सातों संभागीय मुख्यालयों में एक ही समय, एक ही लय, एक ही ताल पर 6000 से अधिक महिलाओं और युवतियों ने जब घूमर किया, तो ऐसा लगा जैसे पूरा प्रदेश किसी अद्भुत सांस्कृतिक तरंग में डूब गया हो। यह केवल एक नृत्य नहीं था; यह राजस्थान की परंपरा, उसकी नारी-शक्ति और उसकी अमर लोक-संस्कृति का विराट उत्सव था, जिसने पूरे प्रदेश को एक साथ जोड़ा और इस जुड़ाव को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी दर्ज किया।

जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का दृश्य तो और भी मनमोहक था। मंच पर पारंपरिक नगाड़ों की धुन गूंजी और डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने खुद इसे बजाकर महोत्सव की शुरुआत की। उनके चेहरे पर वही सौम्यता, वही गरिमा और वही शाही सादगी थी जिसके वह लिए जानी जाती हैं, लेकिन आज उनमें एक अलग चमक थी—राजस्थान की संस्कृति को विश्वपटल पर नए रूप में स्थापित करने का उत्साह। उनके साथ सांसद मंजू शर्मा और कई प्रसिद्ध महिलाएँ भी उपस्थित थीं, जिनकी मौजूदगी ने कार्यक्रम को और गरिमामय बना दिया।

महोत्सव का आरंभ हुआ घूमर की सबसे

प्राचीन शैली से—"एक बार हो पिया जयपुर शहर पधार जो"—और इस गीत की गूंज के साथ हजारों महिलाओं की फिरकीदार घूमर जब एक साथ हवा में बही, तो जमीन पर रंगों का ऐसा सैलाब फैल गया जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता था। केवल जयपुर में ही 1500 महिलाएँ एक साथ मंच पर उतरीं, उनकी रंग-बिरंगी राजपूती पोशाकें हवा में ऐसे लहराईं जैसे मरुस्थल में खिल उठे हों सैकड़ों रंगों के फूल।

हर घाघरा, हर ओढ़नी, हर कलाई का झुनझुनाता कंगन—सब मिलकर एक ऐसी दृश्य-सरिता बना रहे थे जिसे शब्दों में बाँध पाना आसान नहीं। इन रंगों के बीच जब दीया कुमारी स्वयं घूमर की लय में रम गईं, तो यह दृश्य और भी जीवंत हो उठा। नृत्य में उनकी सहजता, विनम्रता और परंपरा के प्रति सम्मान ने लोगों के दिल जीत लिए। शाही परिवार की सदस्या होने के बावजूद उनकी संस्कृति के प्रति यह निकटता और अपनापन हमेशा उनके व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहा है, और आज यह फिर पूरी तरह दिखाई दिया।

एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र जब दीया कुमारी को सौंपा गया, तो हजारों महिलाओं की तालियों में वह गर्व था जो राजस्थान की सैकड़ों वर्षों से चली आ रही कला परंपरा का सम्मान है। यह केवल रिकॉर्ड नहीं था; यह उन अनगिनत राजस्थानी माताओं-बहनों की मेहनत, समर्पण और कला का सम्मान था जो पीढ़ियों से घूमर को जीवित रखे हुए हैं।

महोत्सव में शामिल सभी महिलाएँ पारंपरिक राजपूती वेशभूषा में थीं—घाघरा-ओढ़नी, चूड़ियाँ, कांच की जुदाई, बाजूबंद और पायल की छनछनाहट—सब मिलकर दृश्य को किसी प्राचीन लोक-गाथा जैसा बना रहे थे। लोकगीतों की आवाज और घूमर की लय के बीच किसी को भी यह अनुभव हो सकता था कि समय मानो कुछ क्षणों के लिए थम गया है, और राजस्थान अपनी आत्मा के सबसे सुंदर रूप में सामने खड़ा है।